

साप्ताहिक

शांति मिशन

नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक-41

10 - 16 अक्टूबर 2021

पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

स्वास्थ्य संकटों के इस दौर में

पृष्ठ-6

सिकुड़ते मध्य वर्ग का संकट

पृष्ठ-7

भाजपा की राह पर चलते हुए कांग्रेस का पंजाब में बदलाव का प्रयाग

क्या चन्नी कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक साबित होंगे?

पंजाब में कांग्रेस ने अमरेंद्र सिंह को हटाकर और एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर जो खेल खेला है उसमें वह कितनी सफल होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा?

राज्यों में विधानसभाओं के जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगते हैं हर सत्ताधारी पार्टी अगला चुनाव जीतने के लिए योजना बनाने में लग जाती है अधिकतर यह देखा गया है कि और कई सालों से यह आम चलन बन गया है कि पार्टी कार्यों की कमियों और राज्य सरकार की नाकामियों का ठिकरा मुख्यमंत्री के सिर फोड़कर दूसरा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और यह बताने की कोशिश की जाने लगती है कि नया मुख्यमंत्री चमत्कार करके पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की क्षमता रखता है, अभी कुछ माह में भाजपा ने पहले उत्तराखंड में यह खेल खेला, फिर कर्नाटक में और फिर उत्तराखंड में यही खेल दोहराया और फिर यही खेल गुजरात में भी खेला गया वहां भी सीएम बदला गया। उत्तर प्रदेश में भी योगी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहत थी उसके लिए उसने मोदी जी के एक विशेष आदमी को राजनीति में शामिल करके उसे एम. एल.सी. की कुर्सी पर केवल इसलिए बैठाया था कि अचानक किसी समय योगी को हटाकर उनकी गद्दी उस व्यक्ति को दे दी जाएगी, मगर योगी भाग्यशाली निकले की अचानक आर. एस.एस. चीफ मोहन भागवत उनका सहायता में आ खड़े हुए, फिर किसकी क्या मजाल कि उन पर हाथ डाल सकता, भाजपा की केन्द्रीय नेतृत्व इसी में भलाई समझी कि चुप रहा जाए और वह न सिर्फ यह कि योगी जी के बारे में चुप हो गयी बल्कि ऐलान कर दिया कि यूपी विधान सभा योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।

भाजपा की देखा देखी कांग्रेस में भी यह परंपरा आ गई और उसका पहला शिकार पंजाब के मुख्यमंत्री

कैप्टन अमरिंदर सिंह को होना पड़ा, अमरेंद्र सिंह एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री की पहचान बनाए हुए थे मगर जैसे ही आलाकमान का बदला हुआ तेवर देखा ढेर हो गए, कांग्रेस आलाकमान ने भी मौका गनीमत जाना और पंजाब को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे दिया जो दलित है और अमरेन्द्र सिंह से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, अमरेन्द्र सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने पर अपनी सहमति का इज़हार करके यह इशारा दे दिया कि उनका मतभेद नवजोत सिंह सिद्धू से है, उन्होंने सिद्धू पर आक्रमण तेज़ कर दिए, प्रश्न यह है कि कांग्रेस आलाकमान का चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना उसका

भाजपा की देखा देखी कांग्रेस में भी यह परंपरा आ गई और उसका पहला शिकार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को होना पड़ा, अमरेंद्र सिंह एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री की पहचान बनाए हुए थे मगर जैसे ही आलाकमान का बदला हुआ तेवर देखा ढेर हो गए, कांग्रेस आलाकमान ने भी मौका गनीमत जाना और पंजाब को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे दिया जो दलित है और अमरेन्द्र सिंह से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, अमरेन्द्र सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने पर अपनी सहमति का इज़हार करके यह इशारा दे दिया कि उनका मतभेद नवजोत सिंह सिद्धू से है, उन्होंने सिद्धू पर आक्रमण तेज़ कर दिए, प्रश्न यह है कि कांग्रेस आलाकमान का चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना उसका मास्टर स्ट्रोक है या वह केवल वॉचमैन ही साबित होंगे।

मास्टर स्ट्रोक है या वह केवल वॉचमैन ही साबित होंगे।

पंजाब जहां 32 प्रतिशत शेडयूल कास्ट रहते हैं और जिसकी 117 सीटों में से 34 सीटें आरक्षित हैं वहां एक दलित चन्नी को कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना किसी मास्टरस्ट्रोक से कम नहं है। वह पंजाब के पहले दलित और ज्ञानी जेल सिंह के बाद दूसरे गैर जाट सिख मुख्यमंत्री हे, साम्प्रदायिक मयार बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सिख जाट सुखजेन्द्र सिंह रंधावा और एक हिन्दू ओम प्रकाश सोनी का उपमुख्यमंत्री बनाया है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है, पंजाब में चुनाव लड़ने वाली तमाम पार्टियों समेत भाजपा, अकाली दल, वीएसपी गठबंधन ने

भी किसी एससी को उपमुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था, मगर वह किसी नाम के ऐलान करने से पीछे रह गए और कांग्रेस ने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ही एक दलित को बना दिया।

कांग्रेस का नेतृत्व समझता है कि यह परिवर्तन कर उसने एंटी इंकमबेंसी अर्थात् शासन विरोधी भावना और अमरेन्द्र सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के टकराव से पार्टी को बचा लिया है। एससी सीएम बना कर उन्होंने सब को ख़मोश कर दिया। जो विरोध करना चाहते हैं वह भी अभी विरोध नहीं कर पा रहे। चरणजीत सिंह चन्नी का सीएम बनना एक स्मार्ट मूव है चाहे पार्टी

नेतृत्व वहां झटके और धक्के खाता पहुंचा है। भाजपा ने छह माह के दौरान चार मुख्यमंत्री बदल दिया कहीं फुसफुसाहट नहीं हुई। गुजरात में तो सारा मंत्रीमंडल ही बदल डाला। भाजपा का नेतृत्व जब परिवर्तन करने पर उतर आता है तो कोई अस्पष्टता या हिचकिचाहट नहीं होती। नाम पहले तय होता है। भाजपा नेतृत्व का सत्ताधिकार निर्विवाद है जो कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में नहीं कहा जा सकता इसीलिए इतनी मशक़त करनी पड़ी और पार्टी अभी भी व्याकुल नज़र आ रही है। जो नेतृत्व खुद चुनाव जीतने के अयोग्य है उसकी बहुत ज़बरदस्ती नहीं चलती। इसीलिए अमरेन्द्र सिंह को हटाने का अभियान इतना लंबा चला और अभी भी बहुत कुछ घटित हो रहा है,

गुटबाज़ी बढ़ रही है, नवजोत गुट और कैप्टन गुट रोज़ नीत नए पैतरे आजमा रहे हैं एक दूसरे को धराशायी करने के लिए।

चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन तो गए पर उनके आगे समस्याओं का ढेर है। चुनाव की आचार संहिता लागू होने से लगभग 100 दिन भी नहीं रह गए हैं। चुनाव से पहले इतने कम समय में वह क्या करेंगे यह देखना होगा। वह अमरिंदर सिंह का यह कहकर विरोध करते रहे कि वह वादे पूरे नहीं किए गए। यह ही नवजोत सिद्धू का राग रहा है। अब अपनी बारी है। विशेष शिकायत यह थी कि बेअदबी के मामले में कुछ नहीं किया गया। सिद्धू 'दो

परिवारों की यारी' का भी आरोप लगाते रहे। उनकी शिकायत रही है कि बादल परिवार के खिलाफ़ अमरेंद्र सिंह ने कुछ नहं किया। यह भी शिकायत रही कि ड्रग्स के मामले में छोटी मछलियों को ही पकड़ा गया है, बड़े मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं। अब जबकि सत्ता उनके हाथ आ गई है इसलिए पंजाबियों को आशा होगी कि नई सरकार उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेगी जिन्हें वह खलनाक करार कर चुके हैं। बिजली कंपनियों के साथ समझौते रद्द करने हैं जिसकी ऊंची मांग सिद्धू करते रहे। आगे चलकर किसान आंदोलन क्या शकल अपनाता है यह भी मालूम नहीं। इसके कारण पंजाब में अनिश्चितता बनी हुई है।

जिस तरह ज़बरदस्ती यह परिवर्तन

किया गया है उस से कटुता और दुर्भावना बढ़ी है। अमरेंद्र सिंह की बड़ी शिकायत है कि उन्हें एक बार नहीं तीन बार 'ह्यूमिलियेट' अर्थात् अपमानित किया गया। सिद्धू भी उनकी शान में लगातार गुस्ताखी करते रहे पर उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, उलटा पुरस्कृत किया गया। अमरेंद्र सिंह भी भांपने में असफल रहे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब बच्चे नहीं रहे हालांकि इसी कैप्टन ने 2014 और 2019 में मोदी लहर में कांग्रेस को बचाए रखा था।

अमरेन्द्र सिंह को नीचा दिखाने के लिए उस नवजोत सिद्धू को आगे किया गया जिसका दल बदलने का रिकॉर्ड है और जिसने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वह पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे? अमरेन्द्र ज़ख्मी है जो नए सीएम के शपथ समारोह से उनकी अनुपस्थिति से भी पता चलता है लेकिन अमरेन्द्र सिंह के सामने भी विकल्प सीमित हैं। आयु साथ नहीं है, नई पार्टी खड़ी नहीं कर सकते। भाजपा में जा नहीं सकते। लोकप्रियता में गिरावट आई है। उनके युग का अंत नज़र रहा है पर नवजोत सिंह सिद्धू को वह अवश्य डेमेज कर सकते हैं। कोप भवन में केवल अमरेन्द्र ही नहीं और बहुत सीनियर लीडर हैं। सुनील जाखड़ एक वक्त सीमा निर्वाचित लग रहे थे। मीडिया ने तो यह ख़बर भी दे दी थी कि विधायकों में उन्हें सबसे अधिक समर्थन है लेकिन वह रह गए क्योंकि नवजोत सिंह ने इस कारण विरोध किया कि वह हिन्दू हैं। जहां इससे हिन्दुओं में नाराज़गी बढ़ेगी कि समर्थन हम देते हैं पर हिन्दू सीएम नहीं बन सकता,

बाकी पेज 11 पर

संयुक्त राष्ट्र में तालिबान को लेकर आपत्ति

इसमें शक नहीं कि तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र पहले उन्हें मान्यता दे तो वे दुनिया की सलाह ज़रूर मानेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सामने क़ानूनी विधा यह भी है कि वर्तमान तालिबान मंत्रिमंडल के 14 मंत्री ऐसे हैं, जिन्हें उसने अपनी आतंकवादियों की काली सूची में डाल रखा है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक अधिवेशन में इस बार अफगानिस्तान भाग नहीं ले पाएगा। अशरफ़ ग़नी सरकार ने कुछ सप्ताह पहले कोशिश की थी

कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद अफगानिस्तान को मिले लेकिन वह श्रीलंका को मिल गया। देखिए भाग्य का पुर कि अब अफगानिस्तान को महासभा में सादी कुर्सी भी नसीब नहीं होगी। इसके लिए तालिबान खुद ज़िम्मेदार है। यदि 15 अगस्त को काबुल में प्रवेश के बाद वे बाक़ायदा एक सर्वसमावेशी सरकार बना लेते तो संयुक्त राष्ट्र उनको मान लेता और अन्य राष्ट्र भी उनको मान्यता दे देते। इस बार तो उनके संरक्षक पाकिस्तान ने भी अभी तक औपचारिक

मान्यता नहीं दी है किसी भी देश ने तालिबान के राजदूत को स्वीकार नहीं किया है। वे स्वीकार कैसे करते? खुद तालिबान किसी भी देश में अपना राजदूत नहीं भेज पाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के 76वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपने प्रवक्ता सुहैल

मलेशिया के विपक्षी नेता ने की संसद में चर्चा की मांग

मलेशिया के मुख्य विपक्षी नेता अनवर इब्राहीम ने कहा कि पेंडोरा पेपर खुलासा मामले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि देश के पूर्व वित्त मंत्री और कई मौजूदा अधिकारी इसमें शामिल रह सकते हैं। अनवर इब्राहीम ने कहा कि इस अत्याशयक मुद्दे पर संसद में बहस होना चाहिए क्योंकि इसमें देश के कुछ बड़े नामों का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस क्रम में पूर्व वित्तमंत्री डेम जैनुद्दीन के साथ ही मौजूदा वित्तमंत्री तेंगू जफरुल अज़ीज़ और तीन अन्य नेताओं का नाम लिया।

शाहीन की राजदूत के रूप में घोषणा की है। जब काबुल की सरकार अभी तक अपने आपको अंतरिम कह रही है और उसकी वेधता पर सभी राष्ट्र संतुष्ट नहीं हैं तो उसके भेजे हुए प्रतिनिधि को राजदूत मानने के लिए कौन तैयार होगा? सिर्फ पाकिस्तान और क़तर कह रहे हैं कि शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में बोलने दिया जाए।

वेद प्रताप वैदिक

इमरान ख़ान ने कहा है कि यदि तालिबान सर्वसमावेशी सरकार नहीं बनाएंगे तो इस बात की संभावना है कि अफगानिस्तान में गृहयुद्ध हो जाए। अराजकता, आतंकवाद और हिंसा का माहौल बढ़ सकता है। इसमें

बाक़ी पेज 11 पर

‘पेंडोरा पेपर्स’ में पाकिस्तान के कई कारोबारियों, मंत्रियों के नाम

‘पेंडोरा पेपर्स’ में पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों सेवानिवृत्त सैन्य, असैन्य अधिकारियों, कारोबारियों के नाम आने के बाद प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि देश के जिन जिन नागरिकों के नाम आए हैं, सरकार उनकी जांच करवाएगी। दुनियाभर में चर्चित शख्सियतों के वित्तीय निवेशों को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट (आईसीआईजे) द्वारा ‘पेंडोरा पेपर्स’ नाम से उजागर किए जाने के बाद इमरान ख़ान ने एक बयान में कहा यह कहा। लीक दस्तावेज़ों के मुताबिक वित्त मंत्री शौकत तारिन, जल संसाधन मंत्री मूनिस इलाही, सीनेटर फैसल वावड़ा, उद्योग और उत्पादन मंत्री खुसरो बख़्तियार के परिवार सहित अन्य लोगों के विदेशी कंपनियों से संपर्क पाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरी सरकार पेंडोरा’ पेपर्स में दर्ज देश के सभी नागरिकों की जांच करेगी और यदि कोई ग़लत काम पाया जाता है, तो हम उचित कार्रवाई करेंगे।

ताइवान के खिलाफ़ चीन का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन 52 लड़ाकू विमान भेजे

ताइवान का उत्पीड़न कर रहे चीन ने इस स्वायत्त क्षेत्र के समक्ष अपनी ताक़त का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन करते हुए ताइपे की ओर 52 लड़ाकू विमान उड़ाए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों में 34 जे-16 लड़ाकू विमान और 12 एच-6 बमवर्षक विमान थे। ताइवान की वायु सेना ने चीन के लड़ाकू विमानों को वापस लौटने पर मजबूर किया और अपनी वायु रक्षा प्रणाली पर चीनी युद्धक विमानों की गतिविधियों पर नज़र रखी। चीन ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इन लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा था।

यह दिल्ली है

यह दिल्ली है

यह दिल्ली है

दिल्ली के लुटियंस ज़ोन में हर भवन पर लगा यूनिक क्यूआर कोड, कूड़े वाली गाड़ी बिना रुके नहीं निकल सकती

देश में स्मार्ट बनाने के लिए चुने गए 100 शहरों में से नई दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन यानि एनडीएमसी ने पहली बार स्मार्ट एड्रेसिंग का काम पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में लुटियंस ज़ोन के नाम से ख्यात एनडीएमसी के दायरे वाले 50 हजार से अधिक मकानों को 9 डिजिट का यूनिक एल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आबंटित किया गया है। इस कोड को एनडीएमसी डिजिटल डोर नंबर (एनडीडीएन) नाम दिया गया है। एक छोटी सी स्टील प्लेट पर यह एनडीडीएन अंकित है जो एनडीएमसी के दायरे में आने वाले हर भवन के द्वार पर लगाई गई है। इस प्लेट पर यह एनडीडीएन अंकित है जो एनडीएमसी के दायरे में आने वाले हर भवन के द्वार पर लगाई गई है। इस प्लेट पर बने क्यूआर कोड पर भवन का पूरा ब्यौरा डिजिटल फार्म में दर्ज है। इस कोड को स्कैन करने से न सिर्फ़ उस भवन का पानी, बिजली या गैस का बकाया बिल और बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पता लग सकता है, बल्कि इन सभी पेमेंट्स का पुराना रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है। बिजली, पानी, गैस व अन्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतें भी इसी तंत्र से की जा सकती हैं। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में भी यह क्यूआर कोड क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। जब

कूड़ा एकत्र करने वाली गाड़ी दरवाज़े के बाहर से होकर निकलेगी तो गाड़ी पर लगा स्कैनर 15 मीटर दायरे के एनडीडीएन को स्कैन करता जाएगा। यदि गाड़ी किसी मकान के बाहर बिना रुके निकल जाएगी तो कंट्रोल

रूम को यह पता चल जाएगा कि गाड़ी ने फ्लां दरवाज़े पर रुककर कूड़ा नहीं उठाया। जल्द गूगल मैप पर इसी डेटा से मिलेगा लोकेशन डीडीएन के 9 डिजिट को छोटा

कर केवल 04 डिजिट का किया जा रहा है ताकि आसानी से याद हो सके। जल्द ही यह डेटा गूगल के साथ भी साझा होगा। आने वाले दिनों में डीडीएन से ही घरों को ढूँढने व रास्ता जानने में आसानी होगी। गूगल

पर हर पते के अक्षांश, देशांतर के साथ इमारत की तस्वीर भी होगी ताकि पहचान में गलती न हो।

इसी के साथ एनडीएमसी ने जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 267 स्तर के मैप तैयार किए हैं। एक ही डिजिटल मैप पर सारे पब्लिक टॉयलेट, स्कूल, पार्किंग, स्पोर्ट, हॉस्पिटल, दफ़्तर से लेकर सभी बिजली के खंभों, सीसीटीवी कैमरों तक की जानकारी दी गई है। इसमें खुले और अंडरग्राउंड नालों और अंडरग्राउंड इंटरनेट और बिजली के केबल के अलावा सीवर और गैस पाइपलाइन की भी जानकारी मौजूद है। यूजर चाहे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जानकारी मैप पर देख सकता है। जल्द ही यह हर नागरिक के लिए उपलब्ध होगा।

डीडीएन एक छोटी सी स्टील प्लेट है, जिसे हर घर के दरवाज़े पर लगाया गया है। इसके पहले तीन डिजिट अंग्रेज़ी के एल्फ़ाबेट हैं जो उस इलाके के नाम का शॉर्ट फार्म है, इसके लिए समूचे नई दिल्ली इलाके को 48 छोटे प्रचलित व ऐतिहासिक हिस्सों में बांटकर 48 कोड तैयार किए गए हैं। अगले तीन अंक रोड नंबर हैं और आखिरी तीन अंक मकान नंबर हैं। □□

11 साल में दिए 270 सिविल सेवा अधिकारी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (सौ वर्ष पुराना विश्वविद्यालय) आज़ादी से लेकर अब तक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाकर देश सेवा में अपना अहम योगदान दे रहा है। जामिया की रजिडेंशियल कोचिंग अकादमी बीते लगभग 11 वर्ष से एमसी, एसटी, अल्पसंख्यकों के साथ महिलाओं को मुफ्त कोचिंग देकर प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ने में खासतौर पर काम कर रही है।

यूपीएससी 2020 की 176वीं रैंक प्राप्त सहायनपुर के सरसावां की रहने वाली श्रेया सिंघल ने माना कि यदि जामिया आरसीए नहीं होता तो मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता क्योंकि सुरक्षा के चलते दिल्ली में अकेले तैयारी

करने की अनुमति परिवार कभी नहीं देता। मेरे प्रशासनिक अधिकारी बनने का श्रेय अभिभावकों के साथ-साथ मैं आरसीए को भी दूंगा।

जामिया आरसीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को तीन चरणों में तैयारी करवाई जाती है। किसी भी एक चरण में असफल होने पर आरसीए से बाहर कर दिया जाता है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम) होता है। यदि कोई छात्र प्रीलिम की परीक्षा में सफल नहीं होता है तो उसे अकादमी से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा चरण मुख्य परीक्षा (मैन) है, इसमें भी सफल उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार की तैयारी करवाई जाती है। यहां जनरल स्टूडी, विषय विशेषज्ञता

आदि पर कोचिंग मिलती है। आरसीए के यह चयनित 150 उम्मीदवारों का ग्रुप हॉस्टल, मेस में अपना मैनु खुद तैयार करता है। यहां रहने वाले अधिकतर उम्मीदवार रात-दिन पढ़ाई करते हैं इसलिए वे तला, मसालेदार खाना पसंद नहीं करते हैं। पौष्टिक, कम तेल और मसाले पर आधारित खाना खाया जाता है। इसके लिए प्रति उम्मीदवार 2500 देने होते हैं।

आरसीए हर वर्ष यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग के लिए देशभर से महिला, एससी, एसटी व अल्पसंख्यक समुदाय से 150 उम्मीदवारों का संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन करती है। कठिन प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन

बाक़ी पेज 11 पर

शिक्षा को आंदोलन बनाकर काम काजिए

इस्लाम विश्व का पहला और अकेला धर्म है जिसने शिक्षा प्राप्ति को एक फरीज़ा की हैसियत दी और जिसका हुक्म यह कि जन्म से मृत्यु तक प्राप्त किया जाए। यह भी एक हकीकत है कि इस्लाम की इस हिदायत पर अमल करते हुए मुसलमान ही वह कौम है जिसने इस पूरी दुनिया को शिक्षा और संस्कृति सिखाई और हर पल उसकी रहनुमाई की फिर भी यह बात भी नोट की जाएगी कि अपने देश भारत में आज वही कौम मुस्लिम शिक्षा की दौलत से वंचित हैं बल्कि उनकी महरूमी के नतीजे में गंभीर पिछड़ेपन का भी शिकार है। अल्पसंख्यक आयोग के सर्वे के अनुसार आज भारत में मुसलमान दूसरी समुदाय के मुकाबले दस गुना अधिक पिछड़ेपन का शिकार है। सचर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मुसलमान दलितों से भी बदतर स्थिति में है जिसकी वजह उनका शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाना है।

यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत की आज़ादी के बाद मुसलमान जिन समस्याओं से दोचार है उनमें उनकी तालीमी पिछड़ापन सबसे अहम मसला है औ यह सब जानते हैं कि इस बुनियादी मसला के हल पर ही बाकी तमाम समस्याओं का समाधान टिका है इसलिए कि यही वह चाबी है जिस पर हर मसले का हल छुपा है अब यहां प्रश्न यह है कि आखिर समस्या का समाधान क्या है? सच्ची बात यह है कि जब तक हम शिक्षा को आंदोलन का रूप नहीं देंगे उस समय तक हम इसी सूरतेहाल से दोचार रहेंगे और इस आंदोलन के लिए सबसे अधिक हमें स्वयं अपने बच्चों पर फोकस करना होगा।

तालीमी पिछड़ापन हमारे लिए एक चुनौती की हैसियत रखती है। उसको दूर करने के लिए हमें गंभीरता से बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करना होगा। बच्चों में शिक्षा प्राप्ति की भावना को जगाना होगा। इस विषय में वालिदैन की जिम्मेदारियों की अहमियत है क्योंकि वही बच्चों की शिक्षा बनाने का सही हक अदा कर सकते हैं। मां-बाप, ही बच्चों में शिक्षा की समझ और दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। जैसे-जैसे वह सीख लेते हैं उनमें आत्मनिर्भरता पैदा होती है। आमतौर पर अभी तक बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के बाद समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, या फिर प्राइवेट ट्यूशन लगाना काफी समझते हैं जबकि यह किसी तरह काफी नहीं है। बच्चों की तालीम की बराबर निगरानी ज़रूरी है कम ही वालिदैन बच्चों को उनकी शिक्षा प्राप्ति में समय देते हैं जबकि यह बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर बच्चों माता-पिता अनपढ़ हों तो भी अपने समय का कुछ भाग उनकी निगरानी पर खर्च करें। यह निगरानी भी अति लाभदायक होगी। जो माता पिता अपने बच्चों को समय देते हैं उससे उनके बच्चों में न केवल शौक पैदा होता है बल्कि उनके अंदर आत्मनिर्भरता भी पैदा होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चा शुरू के पांच सालों जो सीखता है बाकी सारी उम्र उसके बराबर सीख पाता है। अगर आरंभिक आयु में तालीम व तर्बियत की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो असली आयु के विपरीत आयु पीछे रह जाती है। अफसोस आयु का यही लाभदायक समय यानि जन्म से पांच-छ वर्ष के समय में हमारी अनदेखी की भेंट चढ़ जाता है।

बच्चों की अच्छी तालीम व तर्बियत के लिए घर के माहौल की काफी अहमियत है। इन दिनों टीवी और मोबाइल का बेजा इस्तेमाल शिक्षा के माहौल को बर्बाद करने में अधिक भूमिका निभाता है इसलिए बच्चों इनके गलत इस्तेमाल से बचाएं। घर का माहौल बच्चों की तालीम व तर्बियत पर अच्छा असर डालता है। इसके विपरीत माता-पिता के रिश्ते बेहतर न हों तो बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही खराब असर पड़ता है।

शिक्षा का अमल जारी रखने के लिए अच्छे घरेलू माहौल के साथ प्यार और हमदर्दी की भी ज़रूरत है। तालीमी निज़ाम में होमवर्क का विशेष महत्व है इससे छात्र की क्षमता और विशेषता का अंदाज़ा होता है। अगर माता पिता शिक्षित हों तो वह इस काम में बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं। अगर वह इस लायक नहीं है तो उन्हें ट्यूटर की सहायता लेनी पड़ सकती है, लेकिन इस सूरत में भी उनकी निगरानी की अहमियत कम नहीं होती। दोनों सूरतों में वालिदैन का बच्चों को समय देना ज़रूरी है। शुरू से ही बच्चों की तालीम व तर्बियत पर ध्यान देने उनको घंटा दो घंटा समय देने से अच्छे परिणाम निकलेंगे, शिक्षा में इंकलाब आएगा।

कुछ वालिदैन अपने बच्चों के खेलने के खिलाफ़ होते हैं, जबकि खेल बच्चों के लिए ज़रूरी है। खेल से न केवल वह जिस्मानी तौर पर स्वस्थ होते हैं बल्कि उनकी मासिक तर्बियत होती है उनके अंदर मुकाबले का जज्बा पैदा होता है इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वह बच्चों की इस भावना के परवान चढ़ने में रुकावट न बनें। अमीर लोग दूसरे ग़रीब बच्चों को जोड़ सकते हैं। ग़रीबी के कारण बहुत से ग़रीब बच्चे या तो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते या बीच में ही तालीम को छोड़ देते हैं, उनमें कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं बल्कि यह कहें कि वह खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। बच्चों की भलाई सोचने वाले भी उनको ड्रापआउट से बचा सकते हैं। बच्चों में शिक्षा को उभारने के लिए यह उनका बड़ा रोल होगा। ऐसे लोग अपने बच्चों की तालीम के साथ उन ग़रीब के लिए आर्थिक सहायता करें तो यह यकीनन बड़ा कार्य होगा। उनकी यह सहायता बेकार नहीं जाएगी।

बच्चों की शिक्षा के लिए बताई गई बातों पर गंभीरता से अमल किया जाए तो बच्चों की शिक्षा में बड़ी प्रगति होगी। अब हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी संजीदगी और अख़लाक का सबूत किस तरह दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर कौम को शिक्षित बनाया जा सकता है और शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाया जा सकता है। यह राय शिक्षा विशेषज्ञों की है और इतिहास उसका गवाह है, जापान की शिक्षा व्यवस्था उसकी रोशन मिसाल है दूसरे विश्व युद्ध में जबरदस्त हार से गुज़रने के बाद शिक्षा के बारे में उसके इंकलाबी फैसले से दुनिया वाकिफ़ है। इस फैसले से उसने तालीम को एक तहरीक बनाकर तरक्कीयाफ़ता देशों में एक अलग स्थान हासिल कर लिया है। इस तरह आज हम भी शिक्षा को एक आंदोलन बनाकर अपना वह खोया हुआ स्थान हासिल कर सकते हैं जो हमें विश्व में प्राप्त था, बुजुर्गों की वह मीरास जो हमने अपनी नासमझी से बर्बाद कर दी है पक्के इरादे और बराबर कार्यों से हम आज एक बार फिर उस मंज़िल को प्राप्त करके अपने आपको अपने बुजुर्गों को सच्चा साबित कर सकते हैं। □□

और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ि अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने जो जौहर दिखलाये तो अल्लाह तआला ने उनके लिए जन्नत में उड़ने के लिए दो बाजुओं का इन्तिज़ाम फ़रमाया कि कहीं भी उड़ कर जाओ और खाओ पीओ, इसी वजह से उनका नाम “जुल जनाहैन” (2 पर वाला) या “त”यार” (उड़ने वाला) रखा गया, यह पैग़म्बर अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सगे भाई, तो यह वाकिफ़ा जुमादल ऊला सन 8 हि0 में पेश आया। (अल बिदाया वन्निहाया, 4/638)

फ़तहे मक्का

इसके बाद रमज़ानुल मुबारक सन 8 हि0 इस्लामी तारीख़ का एक निहायत रोशन मोड़ है, जो सुलह उन्होंने दस साल के लिए की थी और यह तय हो चुका था कि जो क़बीला जिस का साथ देना चाहे दे, बन् ख़ुज़ाआ ने पैग़म्बर अलैहिस्सलाम से और बन् बक्र ने कुरैश से दोस्ती का मुआहदा कर लिया था। इन दोनों क़बीलों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी तो बन् बक्र ने यह सोच कर कि सुलह का ज़माना चल रहा है, मौक़ा ग़नीमत है इस लिए ख़ुज़ाआ से बदला लेना चाहिये, चुनान्चे ख़ुज़ाआ के लोग “वतीर” नाम के एक चश्मे पर ठेकरे हुये थे, बन् बक्र ने अचानक वहाँ पर हमला कर दिया और ख़ुज़ाआ के बहुत से लोगों को मार डाला, और कुरैश के लोगों ने अंदर ख़ाना हथियार वगैरह सपलाई कर के उनका साथ दिया। जब यह वाकिफ़ा पेश आया तो बन् ख़ुज़ाआ के चंद लोग मदीना मुनव्वरा पैग़म्बर अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अज़ किया कि या रसूलल्लाह! हमारे साथ ऐसा जुल्म हुआ, और उन्होंने जंग न करने का मुआहदा तोड़ डाला। अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी थी लेकिन अब अपने दोस्त के साथ ही दुश्मनी हो गई, जब यह बात तय हो गई कि हम आपस में जंग नहीं करेंगे, तो तुम ने बन् बक्र का साथ क्यों दिया?

तो पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने इरादा फ़रमा लिया कि अब उनके साथ आख़िरी दो दो हाथ करने का वक़्त आ गया है, और आप ने तैयारी का हुक्म दे दिया, और अल्लाह तआला से यह दुआ फ़रमाई कि ऐ अल्लाह हमारे इस इरादे की ख़बर किसी भी तरह मक्का वालों को न होने पाये, ताआँकि हम बिल्कुल क़रीब पहुंच जायें, उधर ख़ानदाने कुरैश को एहसास हुआ कि हम से बद अहदी हुई है, तो अब सुफ़ियान खुद मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा आये, उनकी साहब ज़ादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि अल्लाहु अन्हा पैग़म्बर अलैहिस्सलाम के निकाह में आ चुकी थीं, अपनी बेटी से मिलने गए तो बेटी की कुव्वते ईमानी देखिये कि पैग़म्बर अलैहिस्सलाम का बिस्तर बिछा हुआ था, बाप को देखते ही बिस्तर लपेट दिया, पूछा यह क्या हरकत की? बाप का ऐजाज़ होना चाहिये लेकिन आप ने देखते ही बिस्तर लपेट दिया? फ़रमाया कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बिस्तर है, तुम नापाक हो इस पर बैठ नहीं सकते। अगरचे बाप थे, लेकिन पैग़म्बर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत पर हर्ज़ नहीं आना चाहिये, अब सुफ़ियान को बहुत बुरा लगा और कहा कि यहाँ आकर तुम्हारे अख़लाक़ बिगड़ गए। (ज़ादुल मआद मुकम्मल 670,671, अलबिदाया वन्निहाया जि.4 स.672 अर-रहीकुल मख़ूम 615)

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्करे जरीर लेकर मक्का मुअज़्ज़मा ख़ाना हुए, जिस में छः या सात हज़ार अफ़राद थे, और बीच में और क़बाइल आकर मिलते रहे, जब मक्का मुअज़्ज़मा के बिल्कुल क़रीब पहुंच गये तब काफ़िरों को पता लगा कि हुज़ूर यहाँ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सही अंदाज़ा नहीं था, चुनान्चे अब सुफ़ियान और चंद सरदार तहकीक़ करने के लिए रात में निकले तो देखा कि पूरी वादी ख़ेमां से भरी पड़ी है और आग जल रही है, साथियों से मालूम किया कौन है, अचानक इतने लोग कहाँ से आ गए?

इसी दरमियान हज़रत अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हु यह चाहते थे कि मक्का मुअज़्ज़मा के सरदारों को इस्लाम का शर्फ़ और सआदत नसीब हो तो वह लश्कर से हट कर निकल कर आए, और पहचान लिया कि अब सुफ़ियान हैं, पूछा कौन है? कहा कि अब सुफ़ियान? अब सुफ़ियान ने कहा कि तुम कौन? तो जवाब दिया कि मैं अबुल फ़ज़ल हूँ? अब सुफ़ियान ने पूछा कि यह कौन हैं? हज़रत अब्बास ने फ़रमाया कि यह पैग़म्बर अलैहिस्सलाम का लश्कर है, बस फिर तो आँखें फ़टी रह गई, कहा कि अब क्या करें? हज़रत अब्बास ने कहा कि तुम मेरी सवारी पर बैठ जाओ, और मैं तुम्हें हुज़ूर की ख़िदमत में लेकर चलता हूँ, तुम हुज़ूर से अमान ले लो, इसी में ख़ैर है, चुनान्चे अपने पीछे बिठा लिया, चलते रहे, जहाँ आग आती और लोग बैठे हुए मिलते तो वह समझते कि यह तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, पीछे कोई न देखता, जब हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे तो उन्होंने झाँक कर देखा कि पीछे किस को बिठा रखा है? अच्छा अब सुफ़ियान है, उन को पकड़ कर मारो, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी से पैग़म्बर अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में पहुंचे। (ज़ादुल मआद 674, अल बिदाया वन्निहाया जि. 4 स. 683,684 अर-रहीकुल मख़ूम, 624) (जारी)

जो सही रास्ते पर चलेगा जनता उसके साथ रहेगी

महेंद्रनाथ
पांडेय

प्रश्न:- कोरोना संकट से उबरने में भारी उद्योग मंत्रालय ने किस तरह की भूमिका अदा की?

उत्तर:- उस दौर में जब ऑक्सीजन की मांग अचानक काफी बढ़ गई थी, भेल की हरिद्वार इकाई ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और काफी हद तक दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी की। इसी तरह भोपाल और दक्षिण भारत की इकाईयों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया।

प्रश्न:- कोरोना की दूसरी लहर के बाद विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय के मुखिया होने के नाते आप इसे किस रूप में देखते हैं?

उत्तर:- बेशक, कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन भारत सरकार ने इस संकट से पूरी शक्ति के साथ मुकाबला किया। क्या यह सही नहीं है कि इतने बड़े देश में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा? केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने समय

मुझे कतई नहीं लगता कि ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मण हमेशा समग्रता में सोचता है। अपने 44 वर्ष के सामाजिक जीवन में मैंने इसे नज़दीक से महसूस किया है। दरअसल, देश व राज्य में भाजपा की व्यापक स्वीकार्यता से सपा, बसपा हताशा निराश है। छटपटाहट में वे रास्ते ढूँढ रही हैं।

रहते आर्थिक सहायता के साथ ही मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया। बेरोजगारी बढ़ने का विपक्ष का मुद्दा बेबुनियाद है भारी उद्योग मंत्रालय की हाल की पहल ने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की ठोस भूमिका तैयार की है। इसमें लगभग साढ़े चार लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है।

प्रश्न:- ब्राह्मण इन दिनों सियासत की धूरी बने हुए हैं। हर दल उनके पीछे लगा है। ब्राह्मण भाजपा से नाराज क्यों हैं?

उत्तर:- मुझे कतई नहीं लगता कि ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मण हमेशा समग्रता में सोचता है। अपने 44 वर्ष के सामाजिक जीवन में मैंने इसे नज़दीक से महसूस किया है। दरअसल, देश व राज्य में भाजपा की व्यापक स्वीकार्यता से सपा, बसपा हताशा निराश हैं। छटपटाहट में वे रास्ते ढूँढ रही हैं। अफवाह फैलाने की कोशिशें कर रही हैं। वे इसमें कतई सफल नहीं होंगी।

प्रश्न:- सपा, बसपा कहती हैं कि भाजपा ने ब्राह्मण समाज के लिए कुछ नहीं किया? आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों के लिए कौन-कौन से

बीएचयू छात्रसंघ से संसद तक का सफर तय करने वाले डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय फिलवक्त केन्द्र सरकार में भारी उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लगभग 44 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में लगातार द्वा बार से चंदौली से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल, कोरोना काल में भारी उद्योग मंत्रालय की भूमिका, ब्राह्मणों को रिझाने आदि तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश।

काम हुए?

उत्तर:- इसके पहले की सरकारें केवत बातें करती थीं। भाजपा ने इसे करके दिखाया है। ब्राह्मणों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान की बात हो या

फिर संस्कारों को मजबूती देने की।

हर दिशा में काम हुआ है। आर्थिक आधारपर 10 प्रतिशत आरक्षण भाजपा सरकार ने दिया है। पहले केवल आशवासन की घुट्टी पिलाई जाती

थी। अटल जी की सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया था।

प्रश्न:- आखिर विपक्ष को क्यों लगता है कि ब्राह्मण वोट में गुंजाइश

दलित को सीएम बनाने की बात हो तो इसमें ग़लत क्या है, सबका हक़ है : यशपाल आर्य

प्रश्न:- पंजाब में दलित सीएम बनने के बाद उत्तराखंड में भी दलित सीएम का मुद्दा उठा है, छह महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या असर देखते हैं?

उत्तर:- उत्तराखंड में 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 10 प्रतिशत थी और जनजाति की तीन प्रतिशत दस सालों में यह आबादी बढ़ी ही होगी। उत्तराखंड का सियासी इतिहास उठा कर देख लीजिए, राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग जनजाति वर्ग की बहुत निर्णायक भूमिका होती है। यह वग़्र जिस पार्टी के साथ जाता है, उसे जीत मिलती है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली बड़ी कामयाबी में इस वर्ग के समर्थन का बड़ा योगदान रहा है।

प्रश्न:- दलित सीएम की बात कांग्रेस की ओर से उठी है, भाजपा खामोश है। इस पर भाजपा की क्या राय है?

उत्तर:- मैं इसमें नहीं जाना चाहती कि कांग्रेस ने क्या कहा और भाजपा क्या करेगी? यह बहस ही बेमानी है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर दलित सीएम बनाने की बात हो रही है इसमें ग़लत क्या है? मुख्यमंत्री बनने का हक़ हर किसी को है।

प्रश्न:- आप राज्य में सबसे बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं, अगर कांग्रेस आपको सीएम पद का प्रत्याशी बनाने को तैयार हो जाती है तो क्या आप कांग्रेस में वापसी करेंगे?

उत्तर:- पहली बात यह है कि मैं कांग्रेस में वापसी नहीं कर रहा हूँ दूसरी बात, मुख्यमंत्री पद की रेस में मैं शामिल नहीं हूँ। 2017 में जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तो मुझे भाजपा ज्वाइन कराने वाले नेता अमित शाह जी थे। मैंने उस वक्त भी भाजपा में शामिल होने की कोई शर्त नहीं रखी थी। यहां तक मैंने अपने लिए टिकट भी नहीं मांगा था। मेरा बहुत लंबा राजनीतिक

पंजाब में दलित सीएम बनने के बाद उत्तराखंड में भी दलित सीएम के मुद्दे से राजनीति गरमा गई है। 'दलित सीएम' की बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। यशपाल आर्य उत्तराखंड का सबसे कड़ावर दलित चेहरा माने जाते हैं। कांग्रेस में रहते हुए 2012 में वह मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन ऐन वक्त पर मात खा गए। 2017 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और इस समय मंत्री हैं। कांग्रेस ने जब दलित सीएम का कार्ड खेला तो राजनीतिक गलियारों में यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी की चर्चा शुरू हो गई। पेश है इन तमाम सवालियों के जवाब के लिए यशपाल आर्य से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश :-

जीवन है। अलग अलग सरकारों में मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष तक रहा। उत्तराखंड के गठन से अब तक लगातार विधायक हूँ। उससे पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था, अविभाजित यूपी में विधायक रहा था। पद की बहुत अभिलाषा नहीं है, जनसेवा की है, इसलिए राजनीति में हूँ।

प्रश्न:- भाजपा में आप खुश भी तो नहीं बताए जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि भाजपा में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा?

उत्तर:- किसने कहा कि मैं भाजपा में खुश नहीं हूँ? क्या मेरा कोई ऐसा बयान आया, जिसमें यह संकेत जा रहा हो कि मैं खुश नहीं हूँ? क्या मैंने व्यक्तिगत बातचीत में किसी से ऐसा कहा कि मैं खुश नहीं हूँ। यह तो मीडिया की अटकल है कि मैं भाजपा में खुश नहीं हूँ।

प्रश्न:- कांग्रेस ने जैसे ही दलित सीएम का कार्ड खेला, मुख्यमंत्री आपके घर पहुंच गए। कोई वजह तो रही होगी..?

उत्तर:- मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने यह भी बताया कि वह छात्र जीवन से मुझे देखते आ रहे हैं। अगर वह मेरे घर आ गए तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं नाराज हूँ और वह मुझे मनाने आए थे। जैसे मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता। मैं जिस भी पार्टी में रहता हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है, उसका ईमानदारी से पालन करता हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। भाजपा में भी यही कर रहा हूँ।

प्रश्न:- राज्य की राजनीतिक में आपका बहुत लंबा अनुभव है, वहां का चुनावी परिदृश्य क्या देख रहे हैं?

उत्तर:- उत्तराखंड में हमेशा से चुनावी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होती है, इस बार भी इन्हीं दो पार्टियों के बीच होगी।

प्रश्न:- आम आदमी पार्टी कितना असर दिखा सकती है?

उत्तर:- मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव में कोई फैक्टर है।

प्रश्न:- छह माह के अंदर राज्य में दो-दो सीएम बदले गए, उसका असर क्या भाजपा के प्रदर्शन पर पड़ेगा?

उत्तर:- उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। बदलाव को कार्यकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया है चुनाव तो मुद्दों पर होगा।

प्रश्न:- पंजाब में जो बदलाव हुआ, उसका कोई असर उत्तराखंड में चुनाव पर पड़ सकता है।

उत्तर:- यह भविष्य का प्रश्न है। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि पंजाब में दलित सीएम बनाए जाने का उत्तराखंड पर क्या असर होगा और अगर होगा भी तो कितना होगा? राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक राज्य का कोई समीकरण दूसरे राज्य के लिए भी उतना ही प्रभावी हो जाए।

बनी हुई है?

उत्तर:- ये पार्टियां भ्रम में हैं। समाज का हर तबका इनकी हकीकत जान चुका है। मैं पूछता हूँ कि कहाँ गई इनकी विचारधारा? उसे तो तिलांजलि दे दी। एक ने समाजवाद छोड़ दिया, तो दूसरी ने कांशीराम की सोच को भुला दिया। वह हमसे भी ज़्यादा मंदिर-मंदिर दौड़ रहे हैं। हमारी दिशा सही थी। ये तो चुनावी मौसम में राह बदलने वाले लोग हैं। जो स्थायी तौर पर सही रास्ते पर चलेगा, जनता उसके साथ रहेगी।

प्रश्न:- भाजपा में भी बेचैनी आ रही है। आप लोग भी प्रबुद्ध सम्मेलन जोर-शोर से कर रहे हैं?

उत्तर:- बेचैनी नहीं है। हमारे यहां प्रबुद्ध प्रकोष्ठ पार्टी की स्थापना के समय से हैं। भाजपा सतत प्रक्रिया में प्रबुद्धों को जोड़ती रही है। चुनावी मौसम से इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। सभी प्रकोष्ठ सक्रिय हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन भी इसी कड़ी में हैं।

विकास, बेहतर कानून व्यवस्था, कोरोना काल में की गई सेवा, यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश, चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए काम को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा किया जा रहा है।

प्रश्न:- बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीशचंद्र मिश्रा का दावा है कि ब्राह्मण उनके साथ हैं। आपकी क्या राय है?

उत्तर:- वह बसपा को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्राह्मण बसपा से पहले से ही दूर हो चुका है। वर्ष 2007 की परिस्थितियों से आज की तुलना करना बसपा का भ्रम है। 2007 में ब्राह्मणों में कुछ लोग इस सोच के साथ बसपा से जुड़े थे कि सपा सरकार के माफियाराज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा।

प्रश्न:- उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में आपकी पार्टी का प्रमुख मुद्दा क्या होगा?

उत्तर:- विकास, बेहतर कानून व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन, कोरोना काल में की गई सेवा, यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश, चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए काम को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। हम 2022 में 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर फिर से सरकार में आएंगे।

सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का दावा मजबूत

भारत काफी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाने की प्रतीक्षा में है। यह मुद्दा गत दिनों वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक में एक बार फिर उठा।

अब से कुछ वर्ष पहले तक हमारा जो भी नेता विदेश गया या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने भारत का दौरा किया, भारत की विस्तारित सुरक्षा परिषद के लिए उम्मीदवारी के मुद्दे को समर्थन मिला। कम से कम 04 अमेरिकी राष्ट्रपति - जार्ज बुश, बराक ओबामा, ट्रम्प तथा अब जो बाइडेन ने खुलकर शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। नवंबर 2010 में भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान बराक ओबामा ने भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कहा कि वह उस दिन की प्रतीक्षा में है जब भारत सुधरी हुई यू.एन.एस.सी. का एक स्थायी सदस्य बन जाएगा। अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु आपूर्ति समूह तथा सुधरी हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के लिए प्रवेश के अपने समर्थन को फिर दोहराया है।

भारत जून 2020 में 02 सालों के लिए शक्तिशाली सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। इससे पहले भारत 08 बार 02 वर्षीय कार्यकाल की सेवा दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य होने के नाते हमारा मामला मजबूत है। भारत विश्व की दूसर सबसे बड़ी जनसंख्या है तथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए अपना निरंतर योगदान दिया है और 2007 में एक सर्व महिला बल सहित लगभग 02 लाख सैनिक भेज चुका है।

यदि भारत स्थायी सदस्य बनता है तो इसके पास वैश्विक संस्थाओं तथा शासनों को एक नई आकृति देने की क्षमता होगी। गत सितंबर में सुधारवादी प्रक्रिया की धीमी गति से निराश होकर मोदी ने यू.एन.जी.ए. को संबोधित करते हुए पूछा था कि "हमें कब तक प्रतीक्षा करनी होगी?" वर्तमान में परिषद विकासशील जगत तथा वैश्विक ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती - क्योंकि नीतियों का महत्व इसके 05 स्थायी सदस्यों - अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन तथा फ्रांस के हाथों में है। इनमें से कोई एक भी अपनी वीटो की ताकत के साथ किसी प्रस्ताव को नाकाम कर सकता है। 05 स्थायी सदस्यों में से 04 यू.एन.एस.सी. के

लिए भारत के दावे का समर्थन करते हैं, मगर 5 'पी' में से कोई भी परिषद में अपनी वीटो पॉवर वाली सीट को त्यागने की जल्दी में नहीं है। भारत, ब्राजील, जर्मनी तथा जापान, जो

जी-4 नामक दबाव समूह बनाते हैं, परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए मजबूत दावेदार हैं।

परिषद के लिए भारतीय दावेदारी की कहानी प्रधानमंत्री नेहरू के समय

तक पीछे जाती है। नेहरू के आलोचक, तब और अब, उन अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय हितों की बलि देने का आरोप लगाते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि

1950 में संयुक्त राष्ट्र ने चुपचाप नई दिल्ली को परिषद में ताइवान के बदल बारे में चौकस कर दिया था। नेहरू ने इसमें हिचकिचाहट दिखाई तथा सुझाव दिया कि यह चीन को जानी चाहिए। इसी तरह ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने 1955 में सोवियत रूस के प्रस्ताव से भी इंकार कर दिया था। नेहरू ने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को लिखा था "भारत कई कारकों से निश्चित तौर पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का पात्र है लेकिन हम चीन की कीमत पर इसके लिए नहीं जा रहे हैं।" स्वाभाविक है कि उन्होंने चीन के भविष्य के विकास का अनुमान नहीं लगाया था।

वर्तमान रुझान को देखते हुए यह वैश्विक संस्था सुधारों के लिए जल्दी में नहीं है। यद्यपि अमेरिका तथा अन्य देश सुधार की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के लिए यह एक प्राथमिकता नहीं है। पूर्व महासचिव कोफी अन्नान (2015) ने बिल्कुल सही कहा था कि यदि यू.एन.एस.सी. नए स्थायी सदस्यों की नियुक्ति नहीं करती, इसकी प्रधानता को कुछ नए उभरते हुए देशों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। उनका मानना था कि परिषद इस तरह के एक संगठन बन जाएगी जो कमजोर देशों के खिलाफ मजबूत प्रस्ताव, मजबूत देशों के खिलाफ कमजोर प्रस्ताव पारित कर सकता है। यह इस विषय में पी-5 के साथ निपटने में संयुक्त राष्ट्र की असहायता को दर्शाता है।

इसे हम यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं हैं। वैश्विक संगठन का उद्देश्य झगड़ों तथा युद्धों को रोकना था मगर इसके आरंभ से ही 80 झगड़े शुरू हो गए। अमरीकी राष्ट्रपति, बुश से लेकर ट्रम्प तक, सभी ने इसकी कार्य प्रणाली की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र को स्रोतों की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि अमरीका सहित इसके सदस्य समय पर अपना योगदान नहीं चुकाते।

सभी शिकायतों तथा आलोचनाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां विभिन्न देशों के नेता वैश्विक समस्याओं पर काम करने के लिए साथ आते हैं। इस जैसी वैश्विक इकाई बनाने में समय लगता है। इसे नष्ट करने की बजाय सुधारा जाना चाहिए। इसी कारण से भारत संयुक्त राष्ट्र में अपने अधिकारपूर्ण स्थान के लिए लॉबिंग कर रहा है। इसमें सुधार कौन करेगा, वास्तव में एक प्रश्नचिह्न है जिसका उत्तर पी-5 द्वारा दिया जाना चाहिए।

ममता सरकार में शहरी विकास मंत्री बन सकते हैं बाबुल सुप्रियो

ऐसा लगता है कि बाबुल सुप्रियो, जिन्होंने पिछले दिनों भाजपा का दामन छोड़ तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जल्द ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री बन सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि वह शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं जहां उपचुनाव होना है। चर्चा है कि अगर वे जीते तो उन्हें बंगाल में शहरी विकास मंत्री बनाया जा सकता है। उनको यह मंत्रालय मिलना लगभग तय है क्योंकि वह मोदी सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री थे। उनके कार्यों की सराहना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं कर चुके हैं। अपनी नई भूमिका की तैयारी में, सुप्रियो लोकसभा से अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं और बेग और सामान को कोलकाता स्थानांतरित कर के मूड में हैं। अपने घरेलू सामान के अलावा वह अपने 14 पक्षियों और 06 कुत्तों को पहले ही स्पेशल ट्रेन से कोलकाता भेज चुके हैं।

रोज़गार

कैसे हों आईएस- आईपीएस अफसर

हाल ही में यूपीएससी-2020 की सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजे आए हैं। इन परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, वे आईएस, आईपीएस और आईएफएस आदि केन्द्रीय सेवाओं के क्लास-1 अफसर बनेंगे। इन पर ही तमाम सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने की ज़िम्मेदारी होगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश की जान ही होती है उसकी नौकरशाही। अगर ये अपने कामों को सही ढंग से करें, तो देश विकास के रास्ते पर चल पड़ता है और यदि ये भ्रष्ट और काहिल हों जाएं, तो देश को भारी नुकसान और बदनामी होती है। यह सब जानते हैं। फिलहाल तो नए सफल अभ्यर्थियों को बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन देखा जाए, तो इनके लिए असली चुनौती आने वाले समय में तब शुरू होगी, जब ये प्रशिक्षण के बाद जिलों में या अपने विभागों में तैनात होंगे। भारत में ब्रिटिश काल के दौर में जब सिविल सर्विसेज की संकल्पना की गई थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ये अधिकारी ब्रिटिश राज को मजबूत करने व ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों को सख्ती से लागू करने में सहायता करेंगे इसलिए उन्होंने सारे उच्च पदों पर शुरू में तो गोरों को ही तैनात करने की नीति बनाई थी। कहा जाता है कि गोरे अफसर जिस जिले में जिलाधिकारी के तौर पर तैनात होते थे, उस जिले की एक-एक इंच जगह से अच्छी तरह वाकिफ होते थे। उन्हें पता होता था कि जिले में कृषि भूमि

कितने प्रकार की हैं कितनी उपजाऊ है, कितनी बंजर है, कितनी संचित है, कितनी अससंचित है, किस-किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, किस गांव की कितनी आबादी है, उसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना क्या है, जिले में कितनी नदियां और नाले हैं, जिले में औसत वर्षा कितनी होती है? आज के कितने अफसरों को इन सब बातों की जानकारी होगी। जिले को तो छोड़िए, जिस नगर में तैनात हैं, उस नगर में कितने मोहल्ले हैं, यह तक भी उन्हें ठीक से पता नहीं होता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आज़ाद भारत में कुशल और योग्य अफसर हुए ही नहीं। देश ने आज़ादी के बाद अनेक काबिल अफसरों को देखा है। इस लिहाज से जगमोहन से लेकर के. सुब्रमण्यम और ए.के. दामोदर से लेकर एलपी सिंह और टीएन शेषन, जेएन दीक्षित जैसे सैकड़ों सक्षम अफसरों का नाम लिया जा सकता है। पर बहुत से अफसरों का नाम उनकी काहिली और अयोग्यता के लिए भी जाना जाता है वे भ्रष्टाचार में भी आकंठ लिप्त रहे।

एक बात तो समझ ली जाए कि यदि हम अपने सरकारी बाबुओं से बेखौफ होकर काम करने की उम्मीद करते हैं, तो हमें उन्हें उसके लिए आवश्यक माहौल भी देना होगा। आज कितने लोगों को याद है कि सत्येंद्र दुबे और मंजूनाथ की कहानी? सत्येंद्र दुबे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में फैले भ्रष्टाचार को

नज़दीक से देखा। उन्होंने तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक सीलबंद चिट्ठी लिखी जिसमें योजना में भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा था। इस पत्र को लिखने के कारण ही उनकी हत्या हो गई थी। अब बात एस. मंजूनाथ की। वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीली जिले में इंडियन ऑयल कारपोरेशन में कार्यरत थे। 13 सितंबर 2005 को एक पेट्रोल पंप के निरीक्षण के दौरान उन्हें गडबड़ियां मिलीं। बाद में पेट्रोल पंप मालिक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।

लौह पुरुष सरदार पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले बैच के आईएस-आईपीएस अफसरों को स्वराज और सुराज के महत्व पर भाषण दिया था। उन्होंने देश के अफसरों से कहा था कि वे जनता के हितों के लिए काम करें और उसमें किसी तरह की कोताही न बरतें। क्या आज के दिन सभी सरकारी बाबू सरदार पटेल के बजाए रास्ते पर चलते हैं? क्या यह सच नहीं है कि ये बाबू जब जिलों में तैनात होते हैं, तो आम जनता से जितना इन्हें करीब होना चाहिए, उल्टे ये उनसे बहुत दूर हो जाते हैं? मलाईदार पोस्टिंग पाने की फिराक में ही व्यस्त रहते हैं। इस क्रम में वे नेताओं और मंत्रियों के तलवे चाटने से भी परहेज नहीं करते हैं। यह सब कतई स्वीकार न किया जाए, तभी सिविल सेवा परीक्षा से चुनकर आए ये लोग सेवक अपने दायित्व को निभा पाएंगे।

माली में धमाका, संरा के शांति सैनिक की मौत

बमाको : उत्तर पूर्वी माली में हुए आईईडी धमाके में संयुक्त राष्ट्र के एक शांति सैनिक की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय अीयान प्रमुख अल गासिम वने टवीटर पर बताया कि संयुक्त राष्ट्र के वाहन को किदाल क्षेत्र में तेसलित के करीब आईईडी के ज़रिये निशाना बनाया गया, जिसमें एक शांति सैनिक की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हुए।

दक्षिणी यमन के अलगाववादी धड़ों में संघर्ष, दस की मौत

सना : यमन के दक्षिण में स्थित अदन में संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन वाले अलगाववादियों व प्रतिद्वंद्वी समूह के बीच हुई हिंसक झड़प में चार आम नागरिकों समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। झड़प यमन के रिहाइशी इलाके में हुई, जहां राष्ट्रपति आवास व अन्य इमारतें मौजूद हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक झड़प साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल व इसका हिस्सा रहे सशस्त्र समूह के बीच हुई।

अफगानिस्तान पर भारत व जर्मनी के विचार समान

भारत में जर्मनी के राजदूत जे लंडर ने कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर भारत और जर्मनी के विचार समान हैं और दोनों देश इस मसले पर आपसी सहयोग करेंगे। दोनों जर्मनी के एकीकरण की 31वीं वर्षगांठ पर लंडर ने कहा, 'अफगानिस्तान में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। वह वहां विकास कई परियोजनाएं चला रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी अफगानिस्तान में 20 सालों से सक्रिय है इसलिए अफगानिस्तान को लेकर हम दोनों के समान सिद्धांत हैं।

तालिबान ने हथियारों के कारोबार पर लगाई रोक

अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद के हालात में धीरे धीरे ही सही परिवर्तन आने लगा है, छुट पुट घटनाओं को छोड़कर स्थिति पहले से कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है। इस बीच तालिबान के एक रक्षा प्राधिकरण ने अफगानिस्तान में हथियारों के व्यापार पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। स्पूतनिक की रिपोर्ट के अनुसार आदेश को राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है आदेश में अगले सूचना तक हथियारों, गोला बारूद और गैर दस्तावेज़ के वाहनों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया है। स्थानीय समाचार एजेंसी पज़वोक की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पूर्व सरकार से मिले हथियार और वाहनों को उसे सौंपने या सज़ा भुगतने का फरमान जारी किया है बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबानी हुक्मरानों की ओर से अफगानिस्तान में लिए जा रहे फैसलों को लेकर चिंतित है। खासतौर पर महिलाओं की स्थिति व मानवाधिकारों के हनन के पर विशेष नज़दीकी से देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य संकटों के इस दौर में

योगेश कुमार गोयल

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा सहित देश के कई राज्य इस समय डेंगू का दंश झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक करीब तीन हजार मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद, मथुरा और आगरा जिलों में डेंगू से सौ से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन क्षेत्रों में डेंगू के नए स्वरूप 'डी-2' का प्रकोप है, जो डेंगू की अन्य किस्मों से ज़्यादा घातक है। इसे 'डेंगू शॉक सिंड्रोम' से जोड़ कर भी देखा जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कई मरीजों के रक्त नमूनों में डेंगू के इस घातक स्वरूप की पुष्टि हुई है। यह बहुत तेज़ी से फैलता और प्राणघातक साबित होता है। इसमें मरीज को बुखार आने के साथ उसका रक्तचाप अचानक कम हो जाता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा यह प्लेटलेट को भी प्रभावित करता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मरीजों की त्वचा तेज़ बुखार के बावजूद ठंडी महसूस होती है। शॉक सिंड्रोम में मरीज बेचैन हो जाता है और धीरे-धीरे होश खोने लगता है। उसकी नब्ज़ कभी तेज़ चलती है तो कभी धीमी और रक्तचाप कम हो जाता है, जिससे मरीज सदमे में चला जाता है और उसके महत्वपूर्ण अंगों में रक्त संचार कम हो जाता है। कई मामलों में शॉक सिंड्रोम के मरीजों को अस्पताल तब ले जाया जाता है, जब उनकी हालत काफी नाजुक हो चुकी होती है और तब उन्हें बा पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार डेंगू में कोशिकाओं से साइटोकाइन पदार्थ निकलने से रक्तवाहिकाओं को जोड़ने वाली कैपिलरी में स्राव होने लगता है, और रक्त से प्लाज़्मा बाहर निकलने लगता है, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। प्लाज़्मा स्राव होने पर यह फेफड़ों, हृदय तथा पेट की ऊपरी परत पर जमा होने लगता है। एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर लोग डेंगू के मरीजों का इलाज उनकी प्लेटलेट्स की गणना के आधार पर ही करते हैं, जबकि उनकी

प्लेटलेट्स की संख्या पर निगरानी से ज़्यादा ज़रूरी है हेमेटोक्रिट लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा का प्रतिशत है, जो पुरुषों में पैतालीस प्रतिशत और महिलाओं में चालीस फीसद होता है। अगर डेंगू के मरीजों में इसका स्तर सामान्य से अधिक बढ़ने लगे तो इसका अर्थ है कि मरीज की कैपिलरी से रक्त में मौजूद प्लाज़्मा का रिसाव होने लगा है और यह जानलेवा हो सकता है। कैपिलरी वे रक्तवाहिनियां होती हैं, जिनकी दीवार डेंगू में अधिक छिद्रदार हो जाती है, जिस कारण प्लाज़्मा रिसकर शरीर में ही आसपास जमा होने लगता है।

हर मौसम में हर वर्ष डेंगू का ऐसा ही जानलेवा आतंक देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा पनपने से रोकने के लिए समय रहते कोई कारगर क़दम नहीं उठाए जाते। तब प्रशासन गहरी नींद से जागता है। देश के अनेक राज्यों में

प्रतिवर्ष मानसून के बाद देशभर में डेंगू के कई हजार मामले सामने आते हैं और डेंगू की दस्तक के बाद डॉक्टरों तथा प्रशासन द्वारा आम जनता को कुछ हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर और प्रशासन खुद कितने लापरवाह रहे हैं उसका प्रमाण डेंगू फैलने के बाद भी कमोबेश सभी राज्यों में जगह-जगह पर फैले कचरे और गंदगी के ढेर तथा विभिन्न अस्पतालों में सही तरीके से साफ सफाई न होने और अस्पतालों में सही तरीके से साफ सफाई न होने और अस्पतालों में भी मच्छरों का प्रकोप देख कन स्पष्ट रूप से मिलता रहा है।

हर वर्ष इसी प्रकार डेंगू का क़हर देखा जाता है, हजारों लोग डेंगू से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती होते हैं जिनमें से सैकड़ों मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार वास्तव में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का दुष्परिणाम है। अगर प्रशासन हर वर्ष पहले ही दवाओं का छिड़काव कराने के साथ-साथ रोकथाम के लिए अन्य ज़रूरी क़दम उठाए, तो लाखों लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं। प्रशासन की घोर लापरवाही का ही नतीजा है कि विभिन्न राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं, जहां कोई भी गली, मुहल्ला या परिवार ऐसा नहीं बचा है जहां बच्चों से लेकर वृद्ध तक इस बीमारी से ग्रस्त न हुआ हो। हालांकि हर वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता

है, ताकि समय से एहतियाती क़दम उठा कर डेंगू के खतरे को न्यूनतम किया जा सके, लेकिन ज़िम्मेदार लोगों के नकारापन के चलते हर साल डेंगू के जानलेवा आतंक को झेलते रहना ही जैसे आम आदमी की नियति बन गई है। हर वर्ष लगभग सभी जगहों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा डेंगू की रोकथाम के पुख़्ता इंतज़ाम के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब एकाएक डेंगू का जानलेवा आतंक सामने आता है तो ये सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं और स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। वास्तविकता यही है कि अधिकांश स्थानों पर मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए समय रहते संतोषजनक प्रबंध नहीं किए जाते, जिससे सरकारी और निजी अस्पतालों तक में मच्छरों की भरमार नज़र आती है और डेंगू के साथ-साथ चिकनगुनिया, मलेरिया तथा स्वाइन

फ्लू के मामले हर वर्ष सामने आते हैं डेंगू हो या अन्य कोई संक्रामक बीमारी, इनका प्रकोप बढ़ते ही निजी लैबों द्वारा आनन-फानन में जांच की दरें बढ़ा दी जाती हैं और अनेक स्थानों पर तो प्रशासन की मिलीभगत से इन बीमारियों की जांच की आड़ में मरीजों को लूटने का खेल प्रायः बेखौफ़ चलता है।

हर तीन-चार वर्ष के अंतराल पर डेंगू एक महामारी के रूप में उभरता है। करीब तीन वर्ष पहले भारत में डेंगू के एक लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आए थे। तब एम्स में डेंगू के दस सालों के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह तथ्य भी सामने आया कि एम्स में डेंगू से मृत्युदर सात से दस प्रतिशत है। डेंगू अब दिनों-दिन इतना खतरनाक हो रहा है कि कुछ मामलों में यह मरीज को इतनी बुरी तरह अपनी

चपेट में लेता है कि शरीर के अधिकांश अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि पहले जहां डेंगू का असर पन्द्रह-बीस दिनों बार शरीर के अन्य अंगों पर शुरू होता था, वहीं कई मामलों में अब यह एक सप्ताह के अंदर ही किडनी, लीवर और आंतों तक पहुंच जाता है और शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं।

इस समय कई स्थानों पर हालत यह है कि डेंगू के मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, एक-एक बिस्तर पर दो-तीन मरीज हैं और नए मरीजों के भर्ती के लिए जगह नहीं है। प्रतिवर्ष मानसून के बाद देशभर में डेंगू के कई हजार मामले सामने आते हैं और डेंगू की दस्तक के बाद डॉक्टरों तथा प्रशासन द्वारा आम जनता को कुछ हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर और प्रशासन खुद कितने लापरवाह रहे हैं उसका प्रमाण डेंगू फैलने के बाद भी कमोबेश सभी राज्यों में जगह-जगह पर फैले कचरे और गंदगी के ढेर तथा विभिन्न अस्पतालों में सही तरीके से साफ सफाई न होने और अस्पतालों में सही तरीके से साफ सफाई न होने और अस्पतालों में भी मच्छरों का प्रकोप देख कन स्पष्ट रूप से मिलता रहा है। प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि ऐसी कोई बीमारी फैलने के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण कर ज़िम्मेदारी से बचने की होड़ दिखाई देती है। भारत में प्रतिवर्ष डेंगू के हजारों मामले सामने आने और सैकड़ों मौतें होने के बावजूद प्रशासन इससे बचाव के कितने पुख़्ता इंतज़ाम करता है, इसका खुलासा इसी से हो जाता है कि दुनिया में डेंगू का क़हर झेलने वाली कुल आबादी के करीब पचास प्रतिशत मरीज भारत में ही होते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण हमारा स्वास्थ्य ढांचा पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा बोझ झेल रहा है और इसकी तीसरी लहर की चिंता भी बनी हुई है, ऐसे में डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल बुखार आदि बीमारियों से भी एक साथ निबटने में स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह चरमरा सकता है। □□

सिकुड़ते मध्य वर्ग का संकट

ज्योति सिडाना

खास खबरें

फ्रांसीसी चर्च से जुड़े 3,000 लोगों ने बाल शोषण किया

पेरिस : फ्रांस के चर्च के यौन शोषण की जांच कर रहे एक स्वतंत्र आयोग का मानना है कि पिछले 70 सालों में चर्च में 3000 लोगों ने बाल शोषण किया। इन लोगों में एक दो तिहाई चर्च में कार्यरत पादरी थे। आयोग के अध्यक्ष जीन मार्क सॉव ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में यह अनुमान साझा किया है। आयोग ढाई वर्ष से इसकी जांच कर रहा है। सॉव ने कहा, हमने 1950 के दशक के चर्च में काम करने वाले 115,00 पादरियों और चर्च के लोगों का आंकलन किया। इनमें से 3000 लोगों का मूल्यांकन बाल शोषण करने वालों के रूप में किया।

मिलान में विमान हादसे में 8 की मौत

रोम : मिलान के उपनगरीय क्षेत्र में एक छोटा विमान दो मंजिला खाली इमारत से टकरा गया, जिसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई। इटली की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक राहत बचाव दल ने बताया, विमान में सवार पायलट सहित सभी आठ लोग मारे गए हैं। फिलहाल मृतकों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई।

सुरक्षा परिषद की आलोचना से भड़का उ. कोरिया

सियोल : उत्तर कोरिया ने उसके परमाणु मिसाइल प्रक्षेपण कार्यक्रम की आलोचना को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी। यूएनएससी की आपात बैठक में फ्रांस ने कहा था कि वह उ. कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण कार्यक्रम को लेकर चिंतित है। उससे बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले परिषद के प्रस्तावों को लागू करने का आह्वान करता है। इसके जवाब में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर वह उ. कोरिया की संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश करता है, तो भविष्य में नतीजे भुगतने होंगे।

स्कूल खोलने के लिए टीकाकरण का इंतजार ज़रूरी नहीं : विश्व बैंक

विश्व बैंक ने सलाह दी है कि देशों को स्कूल खोलने के लिए पहले व्यापक टीकाकरण किए जाने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण इस ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका कम है। विश्व बैंक की शिक्षा टीम ने दुनियाभर के उन देशों के अनुभव के आधार पर एक नीतिगत नोट तैयार किया है, जहां स्कूल फिर से खोले जा चुके हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि एहतियात के साथ स्कूल खोलने से छात्रों, कर्मचारियों व समाज में संक्रमण फैलने का जोखिम बहुत कम है, इसके लिए बच्चों में संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाना भी ज़रूरी है।

भारत सर्वाधिक मध्यवर्गीय आबादी वाला देश है और यह भी उतना ही सच है कि सबसे ज्यादा गरीब भी यही हैं। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के दौरान दुनियाभर में गरीबी के स्तर पर चले गए लोगों में साठ प्रतिशत भारतीय हैं। इस दौरान भारत में मध्यवर्गीय आबादी में तीन करोड़ से ज्यादा की कमी आई है। जबकि कोरोना से पहले मध्य वर्ग की आबादी लगभग दस करोड़ थी। दूसरी ओर,

के समक्ष एक गंभीर चुनौती भी है क्योंकि मध्य वर्ग ही सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी है जो बाज़ार की दिशा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए मध्य वर्ग का सिकुड़ना न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक चुनौतियों को भी उत्पन्न कर रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2021 में कृषि और बिजली को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों जैसे व्यापार, निर्माण, खनन, विनिर्माण

मध्य वर्ग से अभिप्राय दस से बीस डॉलर रोज़ाना (साढ़े सात सौ रुपए से डेढ़ हजार रुपए) तक की कमाई करने वालों से है। विकासशील देशों के तकरीबन दो-तिहाई परिवारों को कोरोना काल में आमदनी में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। नब्बे के दशक के बाद यह पहला मौका है जब दुनिया में मध्य वर्ग की आबादी में इतनी तेज़ी से गिरावट आई है। प्यू की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में दुनिया में मध्य वर्ग की आबादी तेरह प्रतिशत थी जो 2019 में बढ़कर उन्नीस प्रतिशत हो गई थी।

निर्धन आबादी में साढ़े सात करोड़ की वृद्धि हुई है। अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी दर बढ़कर पन्द्रह प्रतिशत हो गई है शहरी गरीबी दर में लगभग बीस प्रतिशत पर पहुंच गई है। ये आंकड़े इतने भयावह हैं कि इन्हें देख कर ही भविष्य के संकटों और चुनौतियों का अनुमान सहज ही लग जाता है। बढ़ती गरीबी के कारण आबादी का बड़ा वर्ग निराशा के गर्त में जा रहा है। रोज़गार छिन्नने, आय में कटौती होने, जमा पूंजी सिमटते जाने, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक आधारभूत संसाधनों की कमी के कारण लोग खुदकुशी जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं।

मध्य वर्ग से अभिप्राय दस से बीस डॉलर रोज़ाना (साढ़े सात सौ रुपए से डेढ़ हजार रुपए) तक की कमाई करने वालों से है। विकासशील देशों के तकरीबन दो-तिहाई परिवारों को कोरोना काल में आमदनी में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। नब्बे के दशक के बाद यह पहला मौका है जब दुनिया में मध्य वर्ग की आबादी में इतनी तेज़ी से गिरावट आई है। प्यू की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में दुनिया में मध्य वर्ग की आबादी तेरह प्रतिशत थी जो 2019 में बढ़कर उन्नीस प्रतिशत हो गई थी। भारत के संदर्भ में देखें तो महामारी के दौरान देश के 3.2 करोड़ लोगों का मध्य वर्ग की श्रेणी से बाहर होना न केवल चिंता का विषय है, बल्कि भारतीय अर्थ व्यवस्था

क्षेत्र और निजी क्षेत्र को महामारी ने व्यापक रूप से प्रभावित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र के चालीस करोड़ कामगारों में से अधिकांश इन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र की आबादी का बड़ा हिस्सा इस वक्त बेरोज़गारी का सामना कर रहा है। संकट के इस दौर में आय के सभी स्रोत बंद होने के कारण यह वर्ग या तो गरीबी के मुंह में चला गया है या जाने वाला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआई) के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में बेरोज़गारी दर फिलहाल ग्यारह प्रतिशत से अधिक है।

ऐसा नहीं है कि महामारी ने विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के मूलभूत ढांचे पर कम खर्च करने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर महामारी का असर ज्यादा तेज़ी से पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भी स्वीकार किया है कि महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के साढ़े चार प्रतिशत से ज्यादा सिकुड़ने का अनुमान है। यह भी एक तथ्य है कि महामारी से पहले भी यहां व्यापक आर्थिक असमानता और मंदी जैसे संकट मौजूद थे। वर्ष 2018 में देश की कुल संपत्ति का 73 प्रतिशत हिस्सा केवल एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास था, जो 2017 में 58 प्रतिशत हिस्सा था। यह

चौंकाने वाला तथ्य ही है कि सालभर में कुल संपत्ति का पंद्रह प्रतिशत और हिस्सा एक प्रतिशत अमीरों की झोली में पहुंच गया। आज भारत का मध्य वर्ग सिकुड़ता जा रहा है, निम्न वर्ग का विस्तार हो रहा है और ऐसे में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद विश्व में छठे स्थान पर आ गया। जाहिर है, महामारी में भी संपन्न वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु उसकी संपत्ति में तो इज़ाफ़ा ही हुआ है। यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि इस असमानता की जड़ें हमारी आर्थिक नीतियों में ही मौजूद हैं।

कोविड-19 से पहले भारत में महिलाओं में बेरोज़गारी की दर 15 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई। जिन महिलाओं ने अपनी नौकरी नहीं गंवाई, उनको भी अपनी आय में तिरासी प्रतिशत तक की कटौती का सामना करना पड़ा। यानि इस महामारी की मार ने महिलाओं के प्रति असमानता को और भी गहरा कर दिया। इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि मध्यवर्गीय महिलाएं भी परिवार में आर्थिक योगदान करती हैं इसलिए यह भी एक बड़ा कारण है महिलाओं के रोज़गार पर असर पड़ने से परिवार की आमदनी पर भारी असर पड़ा जिसने मध्य वर्ग के आकार को छोटा किया है।

दरअसल, उपभोक्ता संस्कृति के विस्तार के बाद से ही मध्य वर्ग के चरित्र में व्यापक बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे व्यक्तिवादिता का वर्चस्व, एकल परिवार, दिखावे का उपभोग, उच्च प्राप्ति की लालसा इत्यादि। इसके परिणामस्वरूप मध्य वर्ग के सामाजिक सरोकारों में भी बदलाव आया है और सबसे ज्यादा तो वह संवेदनशून्य हो गया है। इसका उदाहरण सामने हैं। किसान आंदोलन, छात्र व शिक्षक आंदोलन, राजनीतिक विरोध, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर विमर्श जैसे पक्षों

शक्ति के संदर्भ में देखें तो निर्धन आबादी सबसे कमज़ोर समूह है। हर प्रकार का अभाव उसे हाशिए पर करता चला जाता है, चाहे फिर प्राकृतिक प्रकोप हों, महामारी हो या समाज द्वारा उत्पन्न आर्थिक असमानता। दरअसल, निर्धनता को असमानता के साथ जोड़ कर देखे जाने की ज़रूरत है। जैसे-तैसे निर्धनता का विस्तार होता है, असमानता और अधिक जटिल होती चली जाती है और फिर इसी से राष्ट्र के समग्र और समावेशी विकास की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

की अनदेखी या उन पर मौन की संस्कृति का समर्थन अब मध्य वर्ग के व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं संभवतः यही कारण है कि वर्तमान संकट के दौर में भी उसने मौन धारण कर लिया है। यहां तक कि अब महंगाई जैसे मुद्दे पर भी मध्य वर्ग की ओर से कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही, जबकि सबसे ज्यादा त्रस्त वही है और इसका सबसे बड़ा खतरा भी उसी पर है।

प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार की आर्थिक नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य वर्ग ने सामाजिक सरोकारों के प्रति भी मौन की संस्कृति अपना ली है। न केवल दूसरों के साथ होने वाली घटनाओं के प्रति अपितु स्वयं या स्वयं के समूहों/समुदायों के साथ होने वाली घटनाओं के प्रति भी अब वह कुछ नहीं बोलता और न ही कोई प्रतिरोध दर्ज कराता है। बढ़ती महंगाई, संसाधनों की अनुपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, बेरोज़गारी शिक्षा का गिरता स्तर व भविष्य की अनिश्चितता, वेतन में मनमानी कटौती, महिलाओं एवं दलितों के लिए असुरक्षित वातावरण, हिंसक घटनाओं में वृद्धि इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मध्य वर्ग शांत है। यह गंभीर स्थिति है जिस पर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को चिंतन करने की आवश्यकता है।

शक्ति के संदर्भ में देखें तो निर्धन आबादी सबसे कमज़ोर समूह है। हर प्रकार का अभाव उसे हाशिए पर करता चला जाता है, चाहे फिर प्राकृतिक प्रकोप हों, महामारी हो या समाज द्वारा उत्पन्न आर्थिक असमानता। दरअसल, निर्धनता को असमानता के साथ जोड़ कर देखे जाने की ज़रूरत है। जैसे-तैसे निर्धनता का विस्तार होता है, असमानता और अधिक जटिल होती चली जाती है और फिर इसी से राष्ट्र के समग्र और समावेशी विकास की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

शक्ति के संदर्भ में देखें तो निर्धन आबादी सबसे कमज़ोर समूह है। हर प्रकार का अभाव उसे हाशिए पर करता चला जाता है, चाहे फिर प्राकृतिक प्रकोप हों, महामारी हो या समाज द्वारा उत्पन्न आर्थिक असमानता। दरअसल, निर्धनता को असमानता के साथ जोड़ कर देखे जाने की ज़रूरत है। जैसे-तैसे निर्धनता का विस्तार होता है, असमानता और अधिक जटिल होती चली जाती है और फिर इसी से राष्ट्र के समग्र और समावेशी विकास की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

गैर मुस्लिमों के साथ रहमतुललिल आलमीन का सद्व्यवहार

सैयद कमरुल हसन

पिछले अंक का शेष

आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के अख़लाक की बेहतरीन प्रशंसा हज़रत आएशा (रज़ि०) के इस कथन में है। अनुवाद “यानि कुरआन आप (सल्ल०) का अख़लाक था। आप (सल्ल०) ने दुनिया के सामने महज़ कुरआन की शिक्षा ही नहीं पेश की बल्कि खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण (नमूना) बनकर दिखाया। एक रिवायत में फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने कभी किसी ख़ादिम को नहीं मारा कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया अपनी ज़ात (स्वयं) के लिए कभी किसी ऐसी तकलीफ का इंतकाम (बदला) नहीं लिया जो आपको पहुंचायी गयी हो। इसके अलावा कि अल्लाह की हुरमतों को तोड़ा गया हो और आपने अल्लाह की ख़ातिर इसका बदला लिया हो।

मदीना मुनव्वरा में कबीला बनी जरीक के मशहूर जादूगर लबैद इब्ने आसिम ने यहूदियों की साजिश से आप पर जादू कर दिया जिसके प्रभाव से आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम बीमार हो गए। आप (सल्ल०) पर जो कैफियत तारी हुई थी उसे महसूस करके आप (सल्ल०) परेशान होते रहे और जब इसका प्रभाव बहुत बढ़ा और शिदत (तेजी) अख़्तियार करने लगा तो एक दिन जब आप (सल्ल०) हज़रत आयशा सिद्दीका (रज़ि०) अल्लाह तआला अन्हा के घर पर थे इस मर्ज़ से परेशान होकर आप (सल्ल०) ने बार-बार अल्लाह तआला से दुआ मांगी। अल्लाह तआला की मदद आयी और एक ख़्वाब के जरिए आप (सल्ल०) पर तमाम हकीकत स्पष्ट कर दी गयी। आपको बताया गया कि आप पर सहर (जादू) हुआ है और यह बीमारी उसी का परिणाम है। आप (सल्ल०) ने कुछ सहाबा (रज़ि०) की मौजूदगी में लबीद को बुलाकर उससे पूछताछ की तो उसने अपने गुनाह का एतराफ (स्वीकार) कर लिया। रसूल अल्लाह (सल्ल०) ने उसे कोई सज़ा न दी। और जुर्म साबित हो जाने के बावजूद आप (सल्ल०) ने उसको छोड़ दिया क्योंकि आपकी जात (स्वयं) के लिए किसी से इंतकाम लेना आपको कभी गंवारा न था। यही नहीं बल्कि

आपने इस मामले का चर्चा करने से भी यह कह कर इंकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी है अब मैं नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ लोगों को भड़काऊँ।

यह इस्लामी तारीख़ और रसूल अल्लाह सल्ल० की ज़िन्दगी के कुछ अहम वाक़ेआत में से एक है। जादूगर ने तो अपनी ओर से आप (सल्ल०) को मारने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था और अगर अल्लाह तआला की ख़ास नज़र (स्पेशल दृष्टि) अपने हबीब (सल्ल०) पर न होती तो दुश्मने इस्लाम की साजिश सफल हो गयी थी। दुनिया का कोई भी इंसान होता इस हकीकत पर ख़ामोश न बैठता लेकिन चूँकि यहूदी की यह हरकत खुद आप (सल्ल०) की जात गिरामी के साथ विशेष थी लिहाजा आपने किसी तरह इसको उचित न समझा कि इससे कोई बदला लिया जाए।

आपने अपने लश्कर में आम ऐलान करवा दिया और हिदायत फरमायी कि मक्का में दाखिल होते वक़्त सिर्फ़ उस शख्स पर हाथ उठाएँ जो उनकी राह में बाधा हो और उनका विरोध करें। आप ने माफी और अमन व सुरक्षा का क्षेत्र इस क़दर बढ़ा दिया था कि मक्का में रहने वालों में से सिर्फ़ वही व्यक्ति मारा जा सकता था जो खुद माफी व सलामती की इच्छा न रखता हो और अपनी ज़िन्दगी से तंग दुखी हो।

ख़ैर ख़्वाही जान तक के गाहों के वास्ते

जख़्म खा-खा कर दुआ दी ऐसी रहमत किस की है

8 हिजरी है मुसलमानों को लगातार कष्ट पहुंचाने, दीन हक की राह में रुकावटें खड़ी करने और जुल्म व सितम का दौर ठण्डा पड़ चुका है। मुसलमान मक्का में फतेहाना दाखिल हो रहे हैं। मुश्रीकीन मक्का घबराए हुए और ख़ौफज़दा हैं दुनिया इनकी नज़रों में अंधेरी है और रास्ते सीमित। अब सूफियान भी जिन्होंने रसूल अल्लाह (सल्ल०) को बड़ी तकलीफें पहुंचायी थीं प्रभावित होकर इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। आज मुसलमान विजेता और ताकतवर हैं और मुश्रीकीन मक्का बड़े भयभीत हैं सहमे हुए हैं कि देखें आज हम से क्या सलूक होता है। उन्हें डर है कि आज हम जुल्म व ज़्यादती का

हिसाब देना होगा। मगर दूसरी ओर हुस्ने अख़लाक़ और रहमत व दिलदारी का पैकर अल्लाह का प्यारा नबी जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमा चुका है कि मैंने आप (सल्ल०) को रहमतुल आलमीन बना कर भेजा है। आम माफी का ऐलान फरमा रहा है कि (अर्थ) जो अपने घर के दरवाजे बन्द कर ले उसके लिए अमन है जो हरम शरीफ में चला जाएगा उसे अमान मिलेगी।

आपने अपने लश्कर में आम ऐलान करवा दिया और हिदायत फरमायी कि मक्का में दाखिल होते वक़्त सिर्फ़ उस शख्स पर हाथ उठाएँ जो उनकी राह में बाधा हो और उनका विरोध करें। आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने माफी और अमन व सुरक्षा का क्षेत्र इस क़दर बढ़ा दिया था कि मक्का में रहने वालों में से सिर्फ़ वही व्यक्ति मारा जा सकता था जो खुद माफी व सलामती की इच्छा न रखता हो और अपनी ज़िन्दगी से तंग दुखी हो।

आज आपकी रहमतुललिल आलमीनी उफू व दरगुज़र, हुस्ने सलूक और अख़लाक़ करीमाना के मामले कदम-कदम पर नज़र आ रहे थे। साअद इब्ने अबादां (रज़ि०) जो अंसार के दस्ते के अमीर थे अबू सूफियान (रज़ि०) के पास से गुजरे तो कहने लगे कि आज क़त्ल व ख़ुरैजी और बदले का दिन है। अबू सूफियान ने इस की शिकायत रसूल अल्लाह (सल्ल०) से की तो आपने साद (रज़ि०) के वाक्य को नापसंद फरमाया और इरशाद हुआ कि “नहीं आज तो रहम व माफी का दिन है ख़ुरैजी और बदले का नहीं।”

मक्का की विजय के दिन एक व्यक्ति ने आपसे बातचीत की तो उस पर कंपकपी आ गयी। आप (सल्ल०) ने फरमाया डरो नहीं। इत्मीनान रखो! मैं कोई बादशाह नहीं हूँ। मैं तो कुरैश की एक ऐसी औरत का लड़का हूँ जो गोशत के सूखे टुकड़े खाया करती थी।

(इब्ने कसीर जि० 3 पृ० 655)
नबी रहमत (सल्ल०) सहाबा कराम के साथ हरम काबा में मौजूद हैं। तमाम कुरैश भी पंक्तिबद्ध होकर सिर झुकाए हुए खड़े हैं उन्हें मुसलमानों और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) पर ढाए गए अपने सारे जुल्म व सितम याद आ रहे हैं वह



(सूरा अल अलक नं० 96)

अनुवाद और व्याख्या : शैखुल हिन्द र.अ.

भला यह तो बता कि यदि वह बंदा सीधी राह पर हो या वह परहेज़गारी सिखला हो। ऐ आदमी भला यह तो बता कि यदि वह व्यक्ति (नमाज़ से रोकने वाला) झुठलाता हो और मुंह मोड़ता हो (सच्चाई से)।

अर्थात् नेक रास्ते पर होता, भले कार्य सिखाता तो क्या अच्छा आदमी होता। अब जो मुंह मोड़ा तो हमारा क्या बिगाड़ा?

क्या उस व्यक्ति को यह ख़बर नहीं कि अल्लाह देखता है।

अर्थात् इस दुष्ट के उपद्रवों को और उस सज्जन व्यक्ति की विनम्रता और एकांत चित्त उपासना करने को अल्लाह देख रहा है।

कदापि नहीं यदि वह व्यक्ति नहीं रुकेगा तो हम चोटी पकड़ कर घसीटेंगे।

अर्थात् रहने दो यह सब कुछ जानता है, लेकिन अपने विद्रोह से नहीं रुकता। अच्छा अब कान खोलकर सुन ले यदि अपनी शरारत से न हटा, तो हम उसको जानवरों और अपमानित कैदियों के भांति सिर के बाल पकड़ कर घसीटेंगे।

जो कि झूठी गुनाहगार चोटी है।

अर्थात् जिस पर सिर ये चोटी है वह झूठ और गुनाह बाल-बाल में घुस गया है।

अब यह अपनी मजलिस (सभा) वालों को बुला ले। हम भी दोज़ख़ के सिपाहियों को बुलाते हैं।

अबुजहल ने एक बार हज़रत मुहम्मद सल्ल० को नमाज़ से रोकना चाहा। आपने दृढ़ता से जवाब दिया। कहने लगा-क्या आप जानते नहीं कि मक्के में सबसे बड़ी संगति मेरी है। उस पर कहते हैं कि वह अपनी संगति वाले साथियों को बुला ले। हम भी उनके कान ऐंठने के लिए अपने सिपाहियों को बुलाते हैं, देखें कौन जीतता है। कुछ दिन पश्चात् बदर के मैदान में देख लिया कि इस्लाम के सिपाहियों ने उसे किस प्रकार घसीट कर बदर के कुयें में फेंक दिया। परंतु घसीटे जाने का वास्तविक समय आख़िरत है। जब फरिश्ते बड़े अपमान के साथ उसको जहन्नम में धकेल देंगे। हदीस में है कि एक बार अबु जहल हज़रत सल्ल० को नमाज़ में देखकर चला कि अभद्रता करे, लेकिन यहां पहुंचा था कि घबराकर पीछे हट गया और पूछने पर कहा कि मुझे अपने और हज़रत मुहम्मद सल्ल० के बीच एक आग की खंदक दिखाई दी, जिसमें कुछ पंख वाली सृष्टि थी। मैं घबराकर वापस आ गया। हज़ूर ने कहा, अगर वह दुष्ट ज़रा भी आगे बढ़ता, तो फरिश्ते उसकी बोटी-बोटी नोच डालते। तात्पर्य यह है कि आख़िरत से पहले ही दुनिया में उसको इस आयत का छोटा सा नमूना दिखा दिया।

सजदा रुकू नं० 1

कदापि नहीं आप उसका कहना न मानिए और आप सच्चे करते रहिए और (अल्लाह से) समीपता प्राप्त करते रहिए।

अर्थात् उसकी आप हरगिज़ परवाह न करें और उसकी किसी बात पर कान न धरिये, जहां चाहो शौक से अल्लाह की उपासना करो और उसके दरबार में सज्दे करके अधिक से अधिक समीपता प्राप्त करते रहो। हदीस में आया है कि मनुष्य सब हालतों से अधिक सज्दे में अल्लाह के समीप होता है।

शंकाओं से घिरे हुए हैं और प्रतीक्षा में हैं कि आप (सल्ल०) क्या आदेश देने वाले हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) को भी अच्छी तरह ज्ञान था कि यह सब आप (सल्ल०) के दुश्मन हैं और उन्होंने इस्लाम के विरोध में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। आप ने इनसे दर्यापत फरमाया कि तुम्हारा क्या ख़्याल है। आज तुम किस व्यवहार (सलूक) के पात्र हों? उन्होंने जवाब दिया आप करीम हैं हमने हमेशा आप को अच्छा सलूक करने वाला पाया। कुर्बान जाइये आप (सल्ल०) के हुस्ने अख़लाक़ और शान करीमाना पर, इर्शाद होता है। (जाद अल मआवज जि०1 पृ० 424)
आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है जाओ तुम सब आज्ञाद हो। “वही

मक्का निकाला था जहां से उसको किया ऐलान लातशरीब आअदा ने जब जेरे नंगीं आया हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पूरी ज़िन्दगी का सम्पूर्ण नमूना और आपकी बेमिसाल व पाक ज़िन्दगी आपके अख़लाक़ और हुस्ने सुलूक की ज़िया बारयां, दुनिया वालों के दिलों को क़्यामत तक रोशन करती रहेगी। और हम जब-जब इस पाक हस्ती की ज़िन्दगानी मुबारक का मुतालआ करेंगे तब-तब हमें एक नई रोशनी एक नया सबक़ और नई हिदायत मिलती रहेगी। जिस पर अगर हम सबक़ दिल से अमल करें तो बिला शुब्हा (बिना शक) हमारी निजात, आख़िरत और दुनियावी सफलता की ज़मानत दी जा सकती है। □□

आखिर विकल्प क्या है अमरेंद्र के पास?

मुख्यमंत्री पद से हटाए गए कैप्टन अमरेंद्र सिंह के पास विकल्प क्या है? जिस तरीके से कैप्टन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उसकी कैप्टन तो क्या, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। कैप्टन ने कहा भी कि तीन सप्ताह पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया था। वे इस बात से आहत हैं कि मोदी लहर को रोकते हुए पंजाब में कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत दिलवा कर सत्ता में लाने के बावजूद उन्हें ज़लील किया गया।

कैप्टन सबसे ज़्यादा नाराज़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से हैं। उन्होंने अपने मन की टीस को छुपाया भी नहीं है। साफ कहा है कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। सिद्धू का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना ही जैसे उनका लक्ष्य है। सिद्धू के खिलाफ

कैप्टन जिस ढंग से सिद्धू के खिलाफ आक्रामक तेवर रख अपना रहे हैं, उसे देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा है कि क्या वे भाजपा में जा सकते हैं? हालांकि वे स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की वजह से पंजाब में भाजपा की हालत इस समय सबसे ख़राब है। प्रश्न है कि ऐसे में कैप्टन को भाजपा से क्या फायदा होगा?

मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने की उनकी घोषणा को लोग कैप्टन के खुद उनके खिलाफ खड़े होने से जोड़कर देखने लगे हैं। लोग जानते हैं कि कैप्टन ने देश में मोदी लहर के बावजूद पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली को अमृतसर लोकसभा सीट पर एक लाख से ज़्यादा वोटों से मात दी थी। कैप्टन के लिए अगला चुनाव 'करो या मरो' का है।

लेकिन प्रश्न फिर वही है कि कैप्टन के पास विकल्प क्या है? जिस ढंग से वे सिद्धू को देश और पंजाब के लिए खतरा करार दे रहे हैं उससे लगता है कि वे भाजपा को सिद्धू के खिलाफ एक चुनावी मुद्दा दे रहे हैं। कैप्टन जिस ढंग से सिद्धू के खिलाफ आक्रामक तेवर रख अपना रहे हैं, उसे देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा है कि क्या वे भाजपा में जा सकते हैं? हालांकि वे स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की वजह से पंजाब में भाजपा

की हालत इस समय सबसे ख़राब है। प्रश्न है कि ऐसे में कैप्टन को भाजपा से क्या फायदा होगा?

कैप्टन के संबंध भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व से अच्छे हैं। अगर मौजूदा

हालत में कैप्टन केन्द्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए राजी कर लेते हैं तो स्थितियां बदल सकती हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। अगर कृषि कानून वापस

हो जाएं और कैप्टन भाजपा में नहीं जाएं तो भी नई पार्टी का गठन कर कोई चुनावी समझौता कर सकते हैं।

हालांकि अभी कांग्रेस आलाकमान की ओर से चरणजीत चन्नी को

मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा है। इस फैसले से कांग्रेस ने सचमुच विपक्षी दलों से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। भाजपा जहां पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय सांपला को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर अनुसूचित जाति के वोट अपनी ओर खींचने की रणनीति पर काम कर रही थी, वहीं अकाली दल ने बसपा से चुनावी समझौता कर अनुसूचित जाति के विधायक को उपमुख्यमंत्री का पद देने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी तो अभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा ढूँढने में लगी ही है।

ऐसे में कांग्रेस ने पहल करते हुए कैप्टन की जगह अनुसूचित जाति के युवा सिख विधायक चन्नी को मुख्यमंत्री बना कर विपक्षी दलों से यह मुद्दा ही छीन लिया है। कैप्टन भी इस बात को समझ रहे हैं कि अभी चन्नी के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया देना फायदेमंद नहीं होगा। ज़ाहिर है कि राज्य के करीब 32 प्रतिशत

कुल मिलाकर यह कि कांग्रेस को इस समय विपक्षी दलों से ज़्यादा डर कैप्टन से ही है। जहां विपक्षी दल कैप्टन के अगले कदम का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं कैप्टन ने भी खुद को कांग्रेस टैग से बाहर कर लिया है। इतना तो तय है कि कैप्टन अपने सिसवां फार्म हाउस में बैठकर चुपचाप चुनावी तमाशा देखने वालों में नहीं हैं आगे क्या करेंगे? यह जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा।

अनुसूचित जाति के मतदाताओं को वे नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। इसलिए वे सिर्फ सिद्धू पर ही निशाना साध रहे हैं। पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें आरक्षित हैं। आने वाले दिनों में अगर कैप्टन केन्द्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए राजी कर लेते हैं तो राज्य की राजनीति में उनका ग्राफ बढ़ जाएगा और वे इस स्थिति में होंगे कि कांग्रेस के समर्थक विधायकों को अपने पाले में लेकर सरकार गिरवा दें और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। इससे बाज़ी उनके हाथ में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

चुनावी वादे पूरे नहीं करने की वजह से जनता में सत्ता विरोधी भावना देखी जा रही थी। सिद्धू भी चुनावी वादों को लेकर कैप्टन को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं, लेकिन कुर्सी गंवाने के साथ ही लोगों का फोकस कैप्टन से हट गया है और वे सोचने लगे हैं कि आने वाले चार महीनों में चन्नी

बाकी पेज 11 पर

कोरोना के मामलों में गिरावट के बावजूद अभी सतर्कता ज़रूरी है

कोविड टीकाकरण अभियान के आगे बढ़ने के बीच संक्रमण के नए मामलों में गिरावट की खबर यकीनन राहत पहुंचाने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीबी छह महीने के बाद कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 20 हजार के नीचे दर्ज की गई और अब देश में संक्रमण के कुल सक्रिय मामले भी तीन लाख से कम रह गए हैं। यह खबर इसलिए भी सुकूनदेह है कि जिस केरल में अभी सबसे अधिक मामले रोज़ाना आ रहे हैं, वहां भी नए मामलों की संख्या पिछले दिनों घट गए। लेकिन शुरू से न्यूनतम संक्रमण वाले क्षेत्रों में शामिल पूर्वोत्तर के मिजोरम से आ रही खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। महाराष्ट्र और केरल जैसे बड़े प्रदेशों के मुकाबले काफी छोटा मिजोरम आज सर्वाधिक नए मामलों वाले पांच राज्यों में एक हैं पिछले कुछ दिनों से वहां लगातार मामलों में बढ़ोत्तरी देखी गई है। विशेषज्ञ आशंका जता चुके हैं कि जिन इलाकों में दूसरी लहर की शुरुआत में कम मामले सामने आए थे, वहां मुमकिन है डेल्टा वेरिएंट देर से पहुंचा हो, इसलिए चौकस रहने की आवश्यकता है।

देश लगभग लॉकडाउन पूर्व की स्थिति में लौट चुका है। कुछ सावधानियां, सीमाओं के साथ तमाम गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और त्यौहारी मौसम की शुरुआत के कारण शहरी बाज़ारों में भी भीड़ लौटने लगी है। इसके बावजूद नए मामलों में गिरावट संतोष की बात है लेकिन न तो सरकारों को और न ही नागरिकों को यह भूलना चाहिए कि महामारी अभी हमारे बीच बनी हुई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन बार-बार आगाह कर रहा है कि इस पर काबू पाने में अभी लंबा समय लगेगा। फिलहाल टीकाकरण के ज़रिये या पूर्व में संक्रमित हो चुके लोगों के प्रतिरोधी क्षमता अर्जित करने से ही उम्मीदें बांधी जा सकती हैं। चूंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी तक अभी टीके की पहुंच नहीं बन पाई है, ऐसे में मानव समुदाय को लगातार आशंकाओं के बीच ही जीना होगा। जब तक सभी देशों के अधिकतम नागरिक इस वायरस के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता हासिल नहीं कर लेते, हम इस पर नियंत्रण को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते।

इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टीकाकरण

की है। दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व - त्यौहार सामने हैं, इसलिए इस काम में विशेष तेज़ी लानी की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों की तादाद देश में अब भी काफी कम है। फिर हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि 18 से कम आयु वर्ग की हमारी पूरी आबादी पूर्णतः टीकाकारित है। यही नहीं, पिछले नौ माह से देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है और अब तक हम सिर्फ पांच दिन में एक करोड़ से अधिक लोगों को खुराक दे सके हैं। इनमें से भी दो दिन तो विशेष आयोजन के थे। अमेरिका जैसे देश 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर खुराक देने लगे हैं। स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडन ने बूस्टर का टीका लगवा लिया है। ऐसे में, हमें टीकाकरण अभियान को 'इवेंट मैनेजमेंट' के आकर्षण से निकालकर दैनिक धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। यह अच्छी तरह साफ हो चुका है कि हमारी क्षमता एक करोड़ से अधिक लोगों को रोज़ाना टीके लगाने की है। इसलिए तीसरी लहर की आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए पूर्ण टीकाकरण की ओर हमें तेज़ी से बढ़ना होगा। □□

बड़े चौधरी जयंत की ताज़पोशी भाजपा के लिए संकेत

रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आखिरकार पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय के प्रमुख नेता की भूमिका में आ गए हैं। यह भूमिका उनसे पहले उनके दिवंगत पिता अजीत सिंह और उनके दिवंगत दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसे उनके लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। पिछले दिनों बागपत के छपरौली में एक रस्म पगड़ी समारोह में जयंत का औपचारिक रूप से बड़े चौधरी के रूप में अभिषेक कर दिया गया। इस समारोह में पश्चिमी यूपी के कम से कम 36 जाट खापों के प्रमुख के साथ-साथ भारतीय किसान संघ के प्रमुख नरेश टिकैत भी शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्यक्रम में गठवाल खाप के प्रमुख ने भी भाग लिया, जिसने मुजफ्फर नगर में हाल ही में हुई महापंचायत से खुद को दूर कर लिया था, जहां जाट हिन्दुओं और मुसलमानों ने अगले वर्ष के चुनावों में भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकने की कसम खाई थी। 21 मई को बड़े चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया था। रस्म पगड़ी को कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। जैसा कि होता है, राज्य चुनावों से कुछ माह पहले इसे आयोजित करने के पीछे राजनीतिक ताकत का दिखाना भी उद्देश्य होता है। जाट समुदाय मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों से नाखुश हैं और उसने भाजपा को दरवाजा दिखाने के अपने इरादे में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जयंत चौधरी को जाट समुदाय के बड़े चौधरी के रूप में नामित करने के बाद अब जाटों के पास अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक राजनीतिक दल भी है समारोह की रिपोर्टों से पता चलता है कि इस कार्यक्रम में समर्थकों की भारी भीड़ शामिल थी, जिनमें से काफी लोग हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से भी आए थे।

खिलाड़ियों के उपहारों की नीलामी से गंगा निर्मल बनाने की मुहिम

गंगा केवल एक नदी नहीं है वह सदियों से इस देश के लिये जीवदायिनी रही है। इसके तटों पर सभ्यताएं विकसित हुईं और इंसानियत का सफर आगे बढ़ा। आज इसे काल के क्रूर थपेड़ों से बचाने और इसके प्रवाह को गति देने के लिए चौतरफा प्रयास हो रहे हैं और इन प्रयासों की नई बुनियाद डाली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी स्तर पर तो इस काम में उनके नेतृत्व का लाभ मिल ही रहा है। प्रधानमंत्री को जो भी उपहार मिलते हैं उनका ई-ऑक्शन वे इसलिय करवा रहे हैं कि उससे मिली राशि नामामि गंगे परियोजना पर खर्च की जाए।

प्रधानमंत्री के इस प्रयास का देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने भी भरपूर समर्थन किया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और टोक्यो पैरालिंपिक 2020 के अनेक विजेताओं ने प्रधानमंत्री को अपने खेल उपकरण उपहार में दिए। यह सामान अब उन देशवासियों के लिए उपलब्ध है जो खेल जगत् में भारत की उपलब्धियों से खुद को जोड़ कर रखना चाहते हैं। उपलब्धियां भी ऐसी कि दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दें। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को ही ले लीजिए। बिहार के हाजीपुर में जन्मे प्रमोद भगत को पांच वर्ष की आयु में ही पैर में पोलिया हो गया

था, जिसके इलाज के लिए उनकी बुआ उन्हें अपने साथ ओडिशा लेकर चली गईं लेकिन प्रमोद ठीक नहीं हो पाए। दूसरे बच्चों को खेलता देख मन में खेलने की बेचैनी ने उनके हाथ में बैडमिंटन रैकेट थमा दिया। फिर वे भूल गये कि उनकी शारीरिक सीमाएं क्या हैं।

वे खेलते गए और जीतते गए। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुके प्रमोद विश्व

चैम्पियन में चार गोल्ड मैडल जीत चुके हैं। यही कारनामा टोक्यो अ पैरालिंपिक में दोहराकर उन्होंने गोल्ड मैडल जीता। देश के गौरव की पताका प्रमोद ने दुनिया में बार बार लहराया। उन्होंने अपना रैकेट जिससे प्रतियोगिता जीती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेंट कर दिया।

एक घूसे में दिन में तारे दिखाने वाली लवलिना बोरगोहेन के वो ग्लव्स जिन्हें पहनकर उन्होंने टोक्यो पैरालिंपिक

में पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की वे ग्लव्स कोई भी अपने घर ले जाकर उस पर गर्व और खुशी में शामिल हो सकता है जो किसी भी भारतीय के लिये महान उपलब्धि है और यह मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी।

असम की रहने वाली लवलिना टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में अपने दमदार प्रहार से विरोधियों को धूल चटा कर 69 किलोग्राम वर्ग के फाइनल की

ओर बढ़ रही थीं लेकिन एक मुकाबला जीतने की जल्दबाजी में वे गोल्ड हासिल करने का मौका चूक गयीं। फिर भी ओलंपिक पोंडियम पर खड़े होकर पूरी दुनिया में अपने देश की पताका ऊंची करने वाली तीन खिलाड़ियों में वह भी शामिल हुईं। उन्होंने कांस्य पदक जीता।

लवलिना ने खेलों की शुरुआत क्रिक बॉक्सिंग से की थी क्योंकि उनकी दोनों बहनें यही खेल खेलती थीं लेकिन बाद में उन्होंने बॉक्सिंग को अपना लिया। ओलंपिक पदक सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं पूरे देश का भी सपना होता है। अपने सपने के साथ पूरे देश के सपने को पूरा कर लवलिना ने खुद को इतिहास में दर्ज करवा लिया। भारत लौट कर लवलिना ने अपने हस्ताक्षर किए हुए ग्लव्स जिसके सहारे इतिहास रचा प्रधानमंत्री को दिए जो उपहार स्वरूप भेंट किए गए। प्रमोद भगत के रैकेट और लवलिना के दास्तानों को हासिल करने की कोशिशें कोई भी कर सकता है। कोई भी 'pmmementos.gov.in' पर जाकर ई-ऑक्शन में हिस्सा ले सकता है। इन दास्तानों को हासिल कर आप लवलिना की शानदार जीत का हिस्सा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास से यह रकम निर्मल और स्वच्छ गंगा बनाने हेतु 'नमामि गंगे कोश' में जमा की जा रही है। □□

जब बेदी ने साता घंटे में पकाए थे दोस्तों के लिए लजीज़ पकवान

भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने आस्ट्रेलिया में एक बार ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मुदस्सर नज़र और पाकिस्तान के दूसरे क्रिकेटर्स को खाने पर आमंत्रित किया था। इसमें उन्होंने लगभग 25 मेहमानों के लिए लजीज़ पकवान बनाया था। बेदी के द्वारा स्वादिष्ट खाना बनाने का जिक्र उनकी ज़िन्दगी पर आधारित किताब 'द सरदार ऑफ स्पिन : ए सेलिब्रेशन ऑफ द आर्ट एंड ऑफ बिशन सिंह बेदी' में है।

बेदी को 75 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर उनके पूर्व साथी दोस्त और क्रिकेट बिरादरी के प्रशंसकों ने

उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस विशेष किताब में कपिल देव की प्रस्तावना, सुनील गावस्कर, ईएस प्रसन्ना और फारुख इंजीनियर के संदेश तथा नेहा बेदी (उनकी बेटी), सचिन तेंदुलकर बी.एस. चंद्रशेखर, वेंकट सुंदरम, रामचंद्र गुहा, अनिल कुंबले, ग्रेग चैपल और कई अन्य लोगों ने लेख लिख कर योगदान दिया है।

प्रथम श्रेणी के पूर्व क्रिकेटर सुंदरम ने अपना लेख 'बिश : टेकिंग अस फ्रॉम क्लब क्लास टू वर्ल्ड क्लास' में अन्य बातों के अलावा बेदी की खाना बनाने की विशेषता का उल्लेख किया है। सचिन बजाज द्वारा संपादित और

'रोली बुक्स' द्वारा प्रकाशित इस किताब में उन्होंने लिखा, 'मैं आस्ट्रेलिया के तस्मानिया में था तभी फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ बिशन सिंह बेदी थे। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान टीम तस्मानिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए लाउसेस्टन में होगी, और वह उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं।'

उन्होंने लिखा है, 'बेदी ने कहा कि वहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और खाना बनाने का सामान और कुछ बर्तनों के साथ मेरे दोस्त के घर पर मिलेंगे। हम सब साथ मिलकर

बाकी पेज 11 पर

स्वास्थ्य

सात आदतें जो दिल को रखेंगी युवा

जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम सोते या बैठते हैं, जो हम खाते हैं, जीवन-शैली से जुड़ी ये सभी छोटी-छोटी आदतें हमारे दिल की सेहत को सीधे प्रभावित करती हैं। इनमें थोड़ा सा बदलाव लाकर हम अपने दिल को सेहतमंद बना सकते हैं :-

रोज 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बिताएं
शरीर में विटामिन डी की कमी भी दिल की बीमारी का कारण बनती है। इससे कैंसर, डायबिटीज, मोटापे का खतरा भी बढ़ता है। रोज 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बिताने से विटामिन डी की कमी पूरी होगी और तनाव कम होगा। विटामिन डी वाला भोजन जैसे पनीर, संतर का रस, सोया दूध और फिश खाएं।

रोज़ कम से कम 5 गिलास पानी जरूर लें
कैलिफोर्निया की लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया है कि जो लोग दिन में पांच गिलास से अधिक पानी पीते हैं, उनमें दिल का दौरा पड़ने की आशंका दो गिलास से कम पानी पीने वालों की तुलना में आधी होती है। ज़्यादा पानी पीने से शरीर हाईड्रेट बना रहता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। डिहाईड्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन गिर जाता है। ब्लड क्लॉट का जोखिम बढ़ जाता है।
बार-बार यूरिनेट जरूरी
ताइवान यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार लोगों को जब भी पेशाब लगे तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है, तब हार्ट बीट्स बढ़ जाती

है। नसों में खिंचाव होता है। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
प्लास्टिक नहीं कांच और स्टील अपनाएं
प्लास्टिक को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए फेथलेट्स (Phthalates) का उपयोग किया जाता है। यह रसायनों का एक समूह होता है। 50 से अधिक मेडिकल पेपर्स में यह बात सामने आई है कि फेथलेट्स सीधे कार्डियोवस्कुलर हेल्थ को प्रभावित करते हैं इसलिए खाद्य पदार्थों को रखने के लिए स्टील या कांच के बर्तन का उपयोग करें, ये प्लास्टिक से बेहतर हैं।
वीकेंड में भी भोजन का समय न बदलें
कभी-कभी काम के तनाव में या सप्ताह के अंत में लोग अक्सर खाने-पीने का पैटर्न बदल देते हैं।

नियमित समय की जगह देर से खाना और सोना करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार इससे हार्ट सहित शरीर के अन्य अंगों की सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है। अगर आप नियमित से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं या कम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यह दिल के लिए खतरनाक है।
हर घंटे में पांच मिनट जरूर चलिए
50 की आयु के आसपास हृदय की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं। इससे पूरे शरीर में रक्त को पंप करना मुश्किल हो जाता है। इसे डायस्टोलिक डिस्पेंशन कहते हैं। तनाव से भी ऐसा होता है और लगातार बैठे रहने से भी। हावर्ड हेल्थ के अनुसार लगातार एक घंटे

बैठे रहने में 80 कैलोरी, खड़े रहने पर 88 कैलोरी और चलने पर 200 से ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। ऐसे में ऑफिस की डेस्क हो या घर में टीवी देखते समय बीच-बीच में चलना ज़रूरी है।
रात में 11 घंटे का उपवास जरूरी
शरीर के मेटाबोलिक फंक्शंस को रिपेयर करने के लिए उसे रोज़ ब्रेक की ज़रूरत होती है। ऐसे में रोज़ रात उसे कम से कम 11 घंटे आराम देना चाहिए। देर रात के स्नैक्स से बचना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ब्लड फैट, शुगर बढ़ता है, जो सीधे हार्ट की हेल्थ को प्रभावित करता है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि शाम सात बजे के बाद कुछ न खाया जाए। □□

शेष.... 11 साल में....

होता है क्योंकि यूपीएससी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों वाली टीम बेहद कठिन प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, ताकि होनहार छात्रों को सफलता मिल सके।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया देश के हर राज्य और शहर में इस दाखिला प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती है। इसका उद्देश्य दूरदराज़, ग्रामीण व

पिछड़े इलाकों के छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं से जोड़ना है। इसका फायदा अकादमी में ग्रुप डिस्कशन के दौरान दिखता है। अलग अलग राज्य, भाषा, संस्कृति, रहन-सहन वाले उम्मीदवार एक दूसरे के माध्यम से मिनी इंडिया को समझते हैं। दरअसल यही विविधता उनका इंटरव्यू में काम आती है। □□

शेष.... संयुक्त राष्ट्र में तालिबान...

शक नहीं कि तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र पहले उन्हें मान्यता दे तो वे दुनिया की सलाह ज़रूर मानेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सामने कानूनी दुविधा है। यह भी है कि वर्तमान तालिबान मंत्रिमंडल के 14 मंत्री ऐसे हैं, जिन्हें उसने अपनी आतंकवादी सूची में डाल रखा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने कुछ प्रमुख तालिबान नेताओं को विदेश यात्रा की जो सुविधा दी है, वह सिर्फ अगले 90 दिन की है। यदि इस बीच तालिबान का बर्ताव

संतोषजनक रहा तो शायद यह प्रतिबंध उन पर से हट जाए। फिलहाल रूस, चीन और पाकिस्तान के विशेष राजदूत काबुल जाकर तालिबान तथा अन्य अफगान नेताओं से मिले हैं। यह उनके द्वारा तालिबान को उनकी मान्यता की शुरुआत है। वे हामिद करज़ई और डॉ. अब्दुल्ला से भी मिले हैं यानि वे काबुल में मिली-जुली सरकार बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? राष्ट्रहित की रक्षा करना क्या हमारे नेताओं का प्रथम कर्तव्य नहीं है। □□

शेष.... आखिर विकल्प क्या है...

क्या करेंगे? क्या चन्नी 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति के मतदाताओं को कांग्रेस की ओर मोड़ पाएंगे? यह भरोसा कांग्रेस को भी नहीं है। यही वजह है कि जातीय संतुलन साधने के इरादे से जट सिंह सुखजिंदर सिंह रंधावा और हिन्दू चेहरे ओम प्रकाश सोनी को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है। सब जानते हैं कि राजनीति में कोई किसी के साथ नहीं होता। जिस रंधावा ने कैप्टन को हटवाने में सिद्धू का साथ दिया, सिद्धू ने उन्हीं को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कुछ समय तक तो चन्नी के साथ साथे की तरह रहे ताकि लोगों में संदेश जाए कि उन्हें चन्नी से कोई शिकायत नहीं, पर यह ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। सिद्धू को अब चन्नी द्वारा मंत्रीमंडल में

कुछ मंत्रियों पर एतराज़ होने लगा है कि इनको बदलो! दूसरी ओर अमरिंदर भी बात को समझ रहे हैं और वह सिर्फ को निशाना बनाए हुए हैं, और सिद्धू को पाक परस्त करार देते हुए पंजाब के लोगों में उनके खिलाफ़ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कि कांग्रेस को इस समय विपक्षी दलों से ज़्यादा डर कैप्टन से ही है। जहां विपक्षी दल कैप्टन के अगले कदम का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं कैप्टन ने भी खुद को कांग्रेस टैग से बाहर कर लिया है। इतना तो तय है कि कैप्टन अपने सिसवां फार्म हाउस में बैठकर चुपचाप चुनावी तमाशा देखने वालों में नहीं हैं आगे क्या करेंगे? यह जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। □□

शेष.... जब बेदी ने साता घंटे में...

कुछ अच्छा बनाएंगे। बेदी को हमेशा से खाने बनाने का शौक रहा है और मुझे पता था कि वह एक बार फिर स्वादिष्ट खाना बनाएंगे।
भारतीय टीम के साथ 1990 के दशक में मैनेजर के तौर पर जुड़े सुंदरम ने कहा कि हम तीन परिवारों के लोगों ने साथ मिलकर लगभग 25 मेहमानों के लिए खाना बनाया। हमारे पास बर्तन छोटे थे इसलिए कुछ पकवानों को दो-तीन बार में बनाना पड़ा। हमें खाना बनाने में सात घंटे

लगे। सुंदरम ने कहा कि ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मुदस्सर नज़र, शफकत राणा और इकबाल कासिम जैसे कई दिग्गजों सहित मिलनसार पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथयह क्षण काफी आनंददायक था। उन्होंने कहा कि सभी अपने घर से हज़ारों मील दूर आस्ट्रेलिया में आराम से थे और यहां पर हंसी, चुटकुले तथा कहानियां का आदान प्रदान हो रहा था। इन सबसे परे बेदी सब का शानदार तरीके से ख्याल रख रहे थे। □□

शेष.... प्रथम पृष्ठ

यहां सुनील जाखगड़ भी खुली नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व भी जवाबदेह है कि उनका सैक्यूलरिज़्म इतना जाली क्यों है कि वह पंजाब में हिन्दू को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं? सुखजिंदर रंधावा इसलिए नाराज़ है कि वह भी सीएम बनते बनते रह गए क्योंकि उनके मित्र सिद्धू जिनके साथ मिलकर अमरेन्दर के खिलाफ़ अभियान चलाया था, ने ही उनके नाम पर आपत्ति कर दी जबकि उनके घर पर मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई थीं। ब्रह्म महिंद्रा दुखी है कि उनकी वरिष्ठता के बावजूद उन्हें उपमुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। नए मुख्यमंत्री और पार्टी आलाकमान के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी कि सिद्धू को कैसे संभाला जाए? सिद्धू जानते हैं कि उनके कंधे पर बंदूक रख अमरेन्दर सिंह पर निशाना लगाया गया है। अब इस इस्तेमाल की वह कीमत मांग रहे हैं।

यह भी समाचार है कि सीएम न बनाए जाने पर वह बैठक में गुस्से से बाहर आ गए थे। उन्हें मनाने के लिए हरीश रावत को घोषणा करनीपड़ी कि 'चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।' हैरानी है कि हरीश जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ऐसा बेतुका बयान दे रहा है। अगर सिद्धू ने ही चुनाव में चेहरा होना है तो चन्नी क्या झक मार रहे हैं? एक ओर आप यह श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो कि आपने एक एससी कास्ट को सीएम बना दिया तो दूसरी ओर उनके सर पर सिद्धू को बैठा रहे हो? अजीब तमाशा है। सुनील जाखगड़ ने भी टवीट किया है कि 'रावत का

यह बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चकित करने वाला रहा। यह सीएम के सत्ताधिकारी को न केवल खोखला करने वाला है बल्कि इस पद के लिए उनके चुनाव के उद्देश्य को नकारने वाला है।' लेकिन जिस हड़बड़ी में यह चुनाव हुआ है यह तो होना ही था।

हमारे विचार में हालात से ऐसा प्रतीत होता है कि आलाकमान सिद्धू को सीएम बनाना चाहता है पर इस परिस्थिति में बना नहीं सका। हैरानी कि बात है कि सिद्धू के बारे में अमरेंदर सिंह ने कहा कि 'पाकिस्तान की हुकूमत से इनकी नज़दीकी है' को आलाकमान नज़रअंदाज़ कर गया। अमरेन्दर ने तो सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमरेन्दर सिंह की चेतावनी है कि पंजाब में कुछ हो रहा है। टिफिन बम तो मिल ही चुके हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर मुखर सिद्धू पाकिस्तान की शरारत पर कभी मुंह नहीं खोलते। इस खामोशी के कांग्रेस को दो नुकसान होंगे। सिद्धू की इमरान-बाजवा के साथ कथित यारी को भाजपा चुनाव में उछालेगी, केवल पंजाब में ही नहीं बाहर भी कि पंजाब में कांग्रेस का चेहरा वह है कि जिस पर उनका ही पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगा रहा है। दूसरा इसका प्रभाव पंजाब की बड़ी जनसंख्या पर पड़ेगा जो पाकिस्तान की शरार को समझता है। अगर सब कुछ सिद्धू के हवाले कर दिया गया तो कांग्रेस प्रभावशाली शहरी हिन्दू का समर्थन खो बैठेगी। दूसरी ओर अगर चरणजीत सिंह चन्नी को कमज़ोर करने का प्रयास किया

गया तो एस.सी. खफा हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पंजाब में जातियों के झमेले में फंस गई लगती है।
पंजाब में कांग्रेस ने पिटारा तो खोल दिया पर इस में से आखिर में निकलता क्या है कहा नहीं जा सकता। नवजोत सिद्धू को प्रमुखता प्रदान कर नेतृत्व ने ही अस्थिर करने वाला तत्व अंदर दाखिल कर लिया। अभी तक सिद्धू चन्नी को समर्थन दे रहे थे लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। सिद्धू ने जो लड़ाई लड़ी है वह किसी और को स्थायी सीएम बनाने के लिए नहीं लड़ी। अभी से वे प्रभाव दे रहे हैं। कि जैसे यह उनकी सरकार है। अब सिद्धू चन्नी पर प्रभाव बना रहे हैं कि उन्होंने मंत्रीमंडल में कुछ ऐसे नेताओं को शपथ दिला जो दागी है और उनको हटाया जाए। इस तरह अब सिद्धू और चन्नी और सिद्धू और कैप्टन कई गुट सक्रिय हो चुके हैं और आलाकमान को समझ नहीं आ रहा है कि सही कौन और क्या हो सकता है।

बहरहाल अंजाम क्या होता है उसके लिए अधिक इंतज़ार का कष्ट शायद उठाना पड़े। चन्नी को काम के लिए केवल 100 दिन मिले हैं उन्होंने इन सौ दिनों में अगर कुछ कर दिखाया और स्वयं को षड्यंत्रकारियों के जाल से बचाए रखा तो समझ लीजिए कि वह क्षमतावादी मुख्यमंत्री हैं और अगर वह इनसे अपने आपको आज़ाद न कर सके तो आने वाला वर्ष पुरवरी में होने वाला विधानसभा चुनाव न केवल चन्नी सरकार बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए ही पंजाब 'कम पानी' (वॉटर ला) साबित होगा।

शेष.... मंज़ूर पस-मंज़ूर

जैसे आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में नहीं आती, इसलिए सरकार के लिए इस तरह का कोई मुआवज़ा संभव नहीं है। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश सुनाया था कि महामारी कानून के मुताबिक पीड़ित लोगों को मुआवज़ा देना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का दायित्व है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि कोविड से मरने वालों के आश्रितों की आर्थिक सहायता देने के बारे में छह सप्ताह के भीतर दिशा निर्देश जारी किए जाएं। उसी संबंध में केन्द्र सरकार ने यह हलफनामा दायर किया है।

किसी आपदा के कारण लोगों का जीवन संकट में पड़ जाए या

बड़े पैमाने पर लोगों के सामने गुजर बसर की समस्या उत्पन्न हो जाए, तो कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने नागरिकों को ऐसी मुसीबतों से पार पाने में मदद करें। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। उसमें प्राकृतिक आपदाओं की एक सूची तैयार की गई थी। मगर कोरोना जैसी महामारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों का उसमें उल्लेख नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार ने उन नियमों का हवाला देकर अपनी ज़िम्मेदारी से बचने का प्रयास किया था। मगर कोई भी नियम कायदा स्थायी नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव किए ही जाते हैं इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की ज़िम्मेदारी रेखांकित की है। छिपी बात नहीं है कि कोविड की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई और उसमें बहुत सारे परिवार उजड़ गए। बड़े पैमाने पर लोगों के काम धंधे चौपट हो गए। अनेक बच्चे अनाथ हो गए। जिनकी पढ़ाई लिखाई रुक गई, उनका भरण-पोषण मुश्किल हो गया। ऐसे लोगों को उनकी हालत पर नहीं छोड़ा जा

सकता। अब सरकार ने मुआवज़े की रकम तो तय कर दी है, पर अड़चनें फिर भी बनी हुई हैं। हालांकि इतने कम पैसे से गुज़ारे का साधन तलाशना आसान नहीं होगा, फिर भी अगर यह रकम समय पर मिल जाती तो पीड़ितों को सहारा मिलता। यह रकम उन तक कब तक पहुंचेगी, देखने की बात है। सबसे बड़ी अड़चन इसमें यह आने वाली है कि कोरोना से हुई मौतों का सही-सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अनेक राज्य सरकारों का आरोप है कि उन्होंने मौतों के आंकड़े छिपाए हैं। बहुत सारे लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज ही नहीं किया गया। फिर ऐसे ग़रीब लोगों की संख्या भी काफी है जिन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना से हुई अध्यापकों की मौतों को लेकर वहां की सरकार का रुख पता ही चल गया था। ऐसे में राज्य सरकारें मुआवज़े की रकम अदा करने में कितनी संजीदगी दिखाएंगी, कहना मुश्किल है। इसलिए इसे लेकर व्यावहारिक पैमाने की अपेक्षा अब भी बनी हुई है। □□

लखीमपुर: सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार, कहा, बर्बरता से हत्या का है केस, मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराज़गी

लखीमपुर खीरी कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकार लगाई। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें, कोर्ट में यूपी सरकार ने आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि मामला जब 302 का है तो गिरफ्तारी अबतक क्यों नहीं हुई। बता दें कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह नहीं पहुंचा। हरीश साल्वे ने कहा कि आशीष कल 11 बजे तक पेश हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के रुख और रवैए पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि हत्या के गंभीर आरोप हैं। आरोपी चाहे जितने हैं उन पर वैसा एक्शन क्यूं नहीं जैसा होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की गई है। इस मामले में लोकल अधिकारी कैसे निष्पक्ष जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बर्बरता से 8 लोगों की हत्या का मामला है। क्या सीबीआई जांच पर विचार किया गया है। साल्वे ने कहा कि राज्य कि तरु से सीबीआई जांच की कोई मांग नहीं की गई है। राज्य सरकार को थोड़ा वक्त दें, 18 अक्टूबर को सुनवात्र की जाए।

● घट क्यों रहा क़द ● आंदोलन का रास्ता ● आपदा में राहत

घट क्यों रहा क़द

पिछले दशकों में भारतीयों के औसत क़द में हुए बदलावों पर हाल ही में आई एक स्टडी रिपोर्ट न केवल चौंकाने वाली बल्कि कई लिहाज़ से चिंताजनक भी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी की हेल्थ की ओर से की गई इस स्टडी में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 1998-99, 2005-06 और 2015-16 की रिपोर्टों के आधार पर 15 से 25 वर्ष और 26 से 50 वर्ष

किसी समाज में लोगों का क़द का घटना बढ़ना कई सारे कारकों से निर्देशित होने वाली एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। इसे लेकर जल्दबाज़ी में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। न ही ऐसी किसी एक स्टडी को पर्याप्त माना जा सकता है। फिर भी, इस अध्ययन से जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं और वे जिन निष्कर्षों की ओर संकेत करते हैं, उन्हें क़तई नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

की आयु समूहों के पुरुषों और महिलाओं के औसत क़द और उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि 2005-06 से 2015-16 की जिस अवधि में दुनिया के स्तर पर लोगों का औसत क़द बढ़ा है, भारत में लोगों के औसत क़द में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक विशेष बात यह रही कि इस अवधि में समृद्ध तबक़े की महिलाओं के औसत क़द में बढ़ोत्तरी देखी गई।

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

① मनीआर्डर द्वारा ② Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION ③ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण SBI A/c 10310541455 Branch: Indraprastha Estate IFS Code: SBIN0001187

हालांकि एससी/एसटी और सबसे ग़रीब तबक़ों की महिलाओं के औसत क़द में गिरावट दर्ज की गई। 2005-06 से 2015-16 की अवधि की जिन महिलाओं के क़द में कमी देखी गई, वे प्रायः नब्बे के दशक में पैदा हुई पीढ़ी की हैं। यह दशक देश में उदारवादी आर्थिक नीतियों की शुरुआत के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट में संकेत यह किया गया है कि तेज़ आर्थिक बदलावों वाले इस दशक में आबादी के एक हिस्से को आर्थिक अस्थिरता से गुज़रना पड़ा, जिसका नतीजा बचपन में पौष्टिक भोजन के अभाव के चलते लंबाई में कमी के रूप में सामने आया हो सकता है। समृद्ध तबक़े की महिलाओं के औसत क़द में इज़ाफ़ा और कमज़ोर तबक़ों की महिलाओं के औसत क़द में गिरावट जैसे तथ्य भी भोजन की पौष्टिकता की लंबाई निर्धारित करने में अहम भूमिका रेखांकित करते हैं लेकिन इसी रिपोर्ट में पुरुषों के औसत क़द के परीक्षण के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि जिन तबक़ों के औसत क़द में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई, उनमें न केवल आदिवासी और जनरल कटेगरी के लोग हैं बल्कि आबादी का सबसे अमीर हिस्सा भी शामिल है। ज़ाहिर है, किसी समाज में लोगों का क़द का घटना बढ़ना कई सारे कारकों से निर्देशित होने वाली एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। इसे लेकर जल्दबाज़ी में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। न ही ऐसी किसी एक स्टडी को पर्याप्त माना जा सकता है। फिर भी, इस अध्ययन से जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं और वे जिन निष्कर्षों की ओर संकेत करते हैं, उन्हें क़तई नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

ज़रूरी है कि इस दिशा में और रिसर्चों के ज़रिए ठोस निष्कर्षों तक पहुंचने की कोशिश की जाए और उनके अनुरूप नीतियों में आवश्यक बदलाव किए जाएं। इस दरम्यान आबादी के हर हिस्से को उपयुक्त, स्वास्थ्यप्रद भोजन समेत जीवन की

बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयासों पर तो विशेष ध्यान दिया ही जाए।

आंदोलन का रास्ता

किसान आंदोलन के कारण रास्ते बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी स्वाभाविक है। कई माह गुज़र जाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। इसका नतीजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते खुलवाने के लिए सर्वोच्च अदालत पहले भी केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों को आदेश दे चुकी हैं लेकिन अदालत के बार-बार कहने के बाद भी इन राज्य सरकारों की ओर से रास्तों को खुलवाने के ठोस प्रयास होते नहीं दिखे, बल्कि सरकारें किसानों पर दोष मढ़ती रहीं कि वे बातचीत के लिए राज़ी नहीं हैं इसलिए किसानों के साथ ही सरकारों के रुख़ को लेकर भी अदालत कम नाराज़ नहीं है। ग़ौरतलब है कि नए कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान पिछले दस माह से अधिक दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं किसान दिल्ली में न घुस पाएं, इसके लिए पुलिस ने सीमाओं को बंद कर दिया था और जगह-जगह लोहे और सीमेंट के अवरोधक खड़े कर दिए थे। इसलिए किसान सड़कों पर ही बैठ गए और वही अस्थायी ठिकाने भी बना लिए यही स्थिति अभी तक कायम है।

इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की सीमाएं बंद होने और रोज़ाना लगने वाले भारी जाम से लोगों को मुश्किलें तो रही हैं। फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा गुरुग्राम, सोनीपत जैसे शहर दिल्ली से सटे हैं। रोज़ाना बड़ी संख्या में यहां से लोग दिल्ली आते-जाते हैं। पर पिछले दस माह से लोगों को सुबह शाम भारी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़कें बंद होने से कई-कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश का बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक

केन्द्र भी है। दिल्ली और इसके आसपास हज़ारों छोटी और मज़ोली इकाइयां हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाती बेचती हैं। ऐसे में रास्ते बंद होने से उद्योगों को तैयार माल की आपूर्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक संगठनों ने भी रास्ते बंद होने से कारोबार पर असर पड़ने की बात कही। इसलिए इस बात से कोई असहमत नहीं होगा कि रास्ते खुलवाने के लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए। साथ ही किसान संगठनों को इस बारे में सकारात्मक रुख़ दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्थायी रूप से मुख्य राजमार्गों को बाधित करना समस्या का समाधान नहीं है। इससे तो स्थिति दिनोंदिन विकट ही होगी।

नए कृषि क़ानूनों को लेकर किसानों और केन्द्र सरकार के बीच बढ़ता गतिरोध दरअसल दोनों पक्षों की हठधर्मिता का नतीजा है। ग्यारह दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाना हैरानी पैदा करता है। आंदोलनकारी किसानों के मामले में सरकार का रवैया भी चिंताजनक है। लगता है कि सरकार यह मान कर बैठ गई है कि किसान परेशान होकर एक न एक दिन अपने आप लौट जाएंगे। किसान भी इस ज़िद पर अड़ गए हैं कि जब तक सरकार इन कृषि क़ानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। कृषि क़ानूनों को अदालत में चुनौती दी गई है इसलिए अब अदालत का कहना है कि किसानों को फैसला आने तक आंदोलन खत्म करने के बारे में विचार करना चाहिए। रास्ते बंद होने से लोगों को जिन दिक्कतों से रोज़ाना दोचार होना पड़ रहा है, वह गंभीर मामला है। कई बार तो यह भी देखने में आया है कि मरीज़ों को लाने-ले जाने वाले वाहन तक समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। इसलिए जनता को हो रही दिक्कतों के बारे में सरकारें और किसान संगठन अब भी सकारात्मक रूप से नहीं सोचेंगे तो

कैसे काम चलेगा?

आपदा में राहत

आख़िरकार केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा है कि कोविड से हुई मौतों के मामले में आश्रितों को पचास हज़ार रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। यह व्यवस्था केवल अब तक हुई मौतों पर नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगी। राहत कार्य में लगे लोगों के लिए भी मुआवज़ा दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के समय जब संक्रमितों की मौत का आंकड़ा

अनेक राज्य सरकारों का आरोप है कि उन्होंने मौतों के आंकड़े छिपाए हैं। बहुत सारे लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज ही नहीं किया गया। फिर ऐसे ग़रीब लोगों की संख्या भी काफ़ी है जिन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना से हुई अध्यापकों की मौतों को लेकर वहां की सरकार का रुख़ पता ही चल गया था।

लगातार बढ़ रहा था और विभिन्न अध्ययनों से पताचला कि बहुत सारे परिवारों के कमाने वाले सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं, अनेक बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनका भरण-पोषण मुश्किल हो गया है, तब सर्वोच्च न्यायालय में गुहाई लगाई गई थी कि कोविड से मरने वालों के आश्रितों को चार लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाए। मगर तब केन्द्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना

बाकी पेज 11 पर

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक Rs.130/-

6 महीने के लिए Rs.70/-

एक प्रति Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें साप्ताहिक

शांति मिशन

1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in — www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com